7

दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

3 शुरू हुई रजिस्ट्री की कार्रवाई, दो दिन में आठ किसानों ने की रजिस्ट्री, 200 से अधिक दे चुके हैं सहमति

5 सीएम योगी का लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन जारी

8 युवा भारत का जोश

UPHIN51019 | वर्षः 02, अंकः 05 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 29 जुलाई, 2024

अगस्त में होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा

यूपी पुलिस में सिपाही के 60244 पदों पर सीधी भर्ती

लिखित परीक्षा का आयोजन 23 24 25 अगस्त और 30 31 अगस्त 2024 को किया जाएगा।

यह परीक्षा उक्त तिथियों में प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।

लखनऊ,संवाददाता। पेपर लीक के कारण निरस्त की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को फिर से आयोजित करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 60244 पदों पर भर्ती के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती–2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में होगा और प्रति पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बता दें कि पेपर लीक के कारण यह पहले हो चुकी यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह परीक्षा छह माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।

चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे–परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक–19.06.2024 को जारी किए गये हैं। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।

परीक्षाओं की शुचिता से छेड़छाड़ करने पर होगी आजीवन सजा और एक करोड़ का जुर्माना

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश–2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–6, सन 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है।

प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी कर सकेंगे निशुल्क बस यात्रा

परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में होगा और प्रति पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते हैं जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।

साल दर साल यूपी में बढ़ रही तादाद...

पांच साल पहले हुए सर्वे में मिले थे दस लाख बांग्लादेशी नागरिक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में साल दर साल तादाद बढ़ रही है। पांच साल पहले हुए सर्वे में 10 लाख बांग्लादेशी नागरिक मिले थे। तब पुलिस ने अनुमान जताया था कि करीब 3 हजार रोहिंग्या नागरिक भी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके आने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए यूपी मुफीद ठिकाना है। साल दर साल यूपी में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पांच वर्ष पूर्व पुलिस ने प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को चिन्हित करने के लिए सर्वे किया था। तब पुलिस ने अनुमान जताया था कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी और करीब 3 हजार रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। बता दें कि तब पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि केवल लखनऊ में ही करीब एक लाख बांग्लादेशी नागरिकों ने अपना ठिकाना बना लिया है। फैजाबाद रोड स्थित अकबरनगर भी जांच में दायरे में आया था। हालांकि सर्वे के बाद ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

स्थानीय नेताओं ने ही की थी मदद...असम के निवासी होने का दावा

अधिकतर मामलों में पाया गया कि स्थानीय नेताओं ने ही उनके भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने में मदद की थी। इनमें से अधिकतर ने असम के निवासी होने का दावा किया था, जिसकी पड़ताल के लिए पुलिस की टीमें भेजी गई थीं।

हालांकि तमाम स्वयंसेवी संगठनों के विरोध के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बीते वर्ष एडीजी कानून–व्यवस्था रहे प्रशांत कुमार के निर्देश पर रोहिंग्या नागरिकों की धरपकड़ के लिए कई जिलों में अभियान भी चलाया गया था।

रायबरेली में चल रहा था बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का षड्यंत्र

उधर, रायबरेली के सलोन में बनाए गए करीब 20 हजार फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की कड़ियां बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ रही हैं। अब तक की जांच में यह बात सामने आ रही है कि यहां से घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का षडयंत्र चल रहा था। इसके बदले जन सेवा केंद्र (सीएससी) संचालक जीशान खान, सुहेल और रियाज मोटी कमाई कर रहे थे। यही कारण है कि चंद दिनों में तीनों ने अच्छी आमदनी कर ली। पुलिस के अनुसार जीशान ने तो रायबरेली के साथ ही लखनऊ में भी अच्छी प्रॉपर्टी बना ली है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र में सलोन के तार कर्नाटक, केरल और मुंबई से भी जुड़ चुके हैं। इसी महीने कर्नाटक पुलिस ने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक संदिग्ध को दबोचा था। उसका जन्म प्रमाणपत्र भी यहीं से बना था। जांच के लिए टीम रायबरेली पहुंची तो धीरे–धीरे पूरा मामला खुलने लगा।

सर्वाधिक अल्पसंख्यकों के बनाए गए हैं प्रमाणपत्र

पुलिस व प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सलोन से सर्वाधिक अल्पसंख्यकों के ही फर्जी प्रमाणपत्र बनाए गए हैं। इनमें 2023 में मुंबई में पकड़े गए चार बांग्लादेशियों के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले जम्मू में भी पकड़े गए कुछ रोहिंग्या के पास यहां बने जन्म प्रमाणपत्र मिले थे।

वीडीओ सहित चार गिरफ्तार

जांच में पता चला कि ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) विजय सिंह यादव की यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सलोन निवासी सीएससी संचालक मोहम्मद जीशान, रियाज और सुहेल खान ने फर्जी प्रमाणपत्र बनाए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया।

गुमसुम है मासूम, हर जुबां पर सुभाष की बहादुरी के किस्से

आंखें पथराईं...सुधबुध खो बैठी पत्नी कांति

गांव में सुभाष चंद्र की बहादुरी चर्चाएं

सेना भर्ती की दौड़ में आया था प्रथम, गांव में सबका दुलारा था

मित्र रंजीत और हरकेश बताते हैं कि 2016 में मैनपुरी में हुई सेना की भर्ती में शामिल हुए लगगभग 100 युवाओं के बैच में सुभाष प्रथम आया था। इससे पहले हम लोग सुबह ही दौड़ने निकल जाते थे, एक मित्र हरेंद्र भी 2017 में सेना में भर्ती हो गया। सुभाष ने आज भी दौड़ना नहीं छोड़ा था, जब भी वह छुट्टी पर आता तो सुबह दौड़ लगाने जाता था।

हाथरस,संवाददाता। हाथरस के सहपऊ गांव नगला मनी की गलियों में सन्नाटा है, चौक–चौराहों व पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीणों में बलिदानी सुभाष की ही चर्चा हो रही थी। ये उसके साहस और शौर्य को याद कर रहे थे तो परिवार को लेकर भी चिंतित थे। सुभाष की पार्थिव देह बुधवार की शाम को जम्मू से दिल्ली पहुंच गई। अब उनकी पार्थिव देह गांव लाई जाएगी।

बलिदानी सुभाष की पार्थिव देह करीब चार बजे जम्मू से रवाना हुई, उसके बृहस्पतिवार तड़के गांव में पहुंचने की संभावना है। पूरे दिन गांव में सुभाष चंद्र की बहादुरी चर्चाएं होती नजर आईं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित कृष्णा घाटी के बट्टल में मंगलवार तड़के सुरक्षाबलों ने सीमा पार से घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया था।

इस गोलीबारी में सहपऊ क्षेत्र के नगला मनी निवासी सुभाष चंद्र बलिदान हो गए। सूचना पर ग्रामीण, परिचित और रिश्तेदार सुभाष के घर पहुंच गए और परिवार ढाढ़स बंधाया। लांस नायक सुभाष के घर पर रिश्तेदारों की आवाजाही रही। रिश्तेदार दूर–दूराज क्षेत्रों से पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया।

लांस नायक सुभाष चंद्र के बलिदान की खबर से पत्नी कांति देवी सुधबुध खो बैठी है। गुमसुम बैठी पथराई आंखों से वह लोगों को देख रही है। महिलाएं उसे दिलासा देकर संभालने की कोशिश कर रही है। वह आठ माह की गर्भवती है, ऐसे में उसके स्वास्थ्य की भी चिंता है। मंगलवार की रात तक तो परिजनों ने उन्हें सुभाष को गोली लगने की बात बताई थी, लेकिन देर रात उसे उनके बलिदान होने की जानकारी मिल गई। कभी वह बिलखने लगती तो कभी गुमसुम बैठ जाती हैं।

घर में लोगों को देख गुमसुम है रितिका...उसे नहीं पता बलिदान हो गए पिता

सुभाष की डेढ़ साल की बेटी रितिका इस बात से अनजान है कि उसके पिता ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। घर में आने वाले नए –नए चेहरों को देख कर वह गुमसुम है। समझ नहीं पा रही है कि क्या हुआ। वह इतनी छोटी है कि न कुछ पूछने की स्थिति में है और न ही परिजन उसे बताने की स्थिति में है। कुछ देर इधर, उधर घूमने के बाद दादा मथुरा प्रसाद की गोद में बैठ जाती है और वह भी नम आखों से उसे दुलारने लगते हैं।

ढांढस बंधाने पहुंच रहे लोग

क्षेत्र के गांव नगला मनी निवासी सुभाष चौधरी के बलिदान की खबर पर बुधवार सुबह से ही उनके आवास पर लोगों को जमावड़ा लगा रहा। भाजपा नेता प्रीति चौधरी उसके आवास पर पहुंच कर उनके परिवार को सांत्वना दी। जाट महासभा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रताप चौधरी ,सपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि विपिन यादव ने भी परिवार को ढाढ़स बंधाया। सादाबाद एसडीएम संजय कुमार,सीओ हिमांशु माथुर, कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार वर्मा आदि ने गांव में पहुंचे और परिजनों को सांत्वाना दी।

सम्पादकीय

राजनैतिक हथियार बनता केन्द्रीय बजट

लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024–25 का बजट जहां एक ओर देश के मुठ्टी भर लोगों को खुशी और ज्यादातर वर्गों के लिये निराशा लेकर आया है, वैसे ही गिनती के राज्यों को खुश करने वाला जबकि अधिकतर को नाखुश करने वाला साबित हुआ है। सरकार बनाने में मददगार रहे दो राज्यों– बिहार और आंध्रप्रदेश की झोलियों को जिस तरह से केन्द्र सरकार ने भरा है, उससे अनेक राज्यों का मायूस होना स्वाभाविक है। इस बजट में जिस प्रकार से सरकार ने भेदभाव बरता है उससे राज्यों में फूट पड़ने की आशंका है; और उसका सबसे बुरा पहलू यह है कि वह देश की संघीय व्यवस्था पर गहरी चोट है। पिछले 10 वर्षों से देश पर शासन कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य सिपहसालार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अनेक कृत्यों से जिस तरह भारत के संघीय ढांचे की नींव को हिलाकर रख दिया है, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिये। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यदि बजट का इस्तेमाल कर राज्यों का राजनैतिक समर्थन जुटाने की परम्परा चल पड़ी तो केन्द्रीय राजस्व का बंटवारा अलग–अलग राज्यों की ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि सियासी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाने लगेगा। यह व्यवस्था वंचित रह गये राज्यों में असंतोष को जन्म देगा।

उल्लेखनीय है कि आंध्रप्रदेश की तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) के 16 और बिहार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 12 सांसदों (लोकसभा सदस्य) के बल पर मोदी सरकार टिकी हुई है। पहले से ही अंदेशा था कि अपने समर्थन के एवज में इन दोनों ही पार्टियों के नेता, क्रमशः चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार (अपने–अपने राज्यों के मुख्यमंत्री) केंद्र की बांहें मरोड़कर कीमत वसूल करेंगे। इन दोनों नेताओं की अपने–अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग रही है। मांग तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी थी लेकिन वहां अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन गयी है इसलिये वह मसला कम से कम वहां तो खत्म हो गया है। इस बजट में टीडीपी और जेडीयू के प्रति केन्द्र का खास अनुराग झलका है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण 2018 में भाजपा का साथ छोड़कर नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस को टा–टा कर दिया था, इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में फिर से उसका दामन थामा था। तभी से नायडू की मांग थी कि आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य के बन जाने से उन्हें अपनी राजधानी बनाने की ज़रूरत है। इसके लिये 15000 करोड़ रुपये उन्हें दिये गये। उनका खुश होना स्वाभाविक है।

दूसरी खुशी नीतीश बाबू को मिली है। चुनाव के ऐन पहले विपक्षी गठबन्धन इंडिया को छोड़कर एनडीए में 17 महीने बाद वापसी करने वाले नीतीश कुमार को भी पुरस्कार मिला है– 59 हजार करोड़ रुपए का। इसका बड़ा हिस्सा बिहार में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने सम्बन्धी उपायों पर खर्च होंगे। हालांकि इसकी हवा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (सांसद) ने यह कहकर निकाल दी है कि जब तक नेपाल और उप्र से बिहार को जाने वाली नदियों की बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक बिहार की नदियों की बाढ़ को नियंत्रित कर पाना असम्भव है। जिस तरह से चंद्रबाबू अब विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात भूल गये हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी इससे इतने गदगद हैं कि वे पत्रकारों से कह रहे हैं कि, 'वे तो पहले से कह रहे थे कि उन्हें या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज।

केन्द्र ने यह राशि तो दे ही दी है।' हालांकि वे भूल रहे हैं कि इससे बड़ी राशि का ऐलान तो मोदी राज्य की अपनी प्रचार सभाओं में करते रहे थे। बहरहाल, यह भी सच है कि यह राशि राज्य द्वारा केन्द्र की देखरेख और निर्देश पर ही खर्च करनी होगी। जो भी हो, यह आवंटन नीतीश को अपना चेहरा छिपाने और इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल होने के फैसले को सही ठहराने के लिये काफी है।

केन्द्रीय बजट एक साझा सम्पत्ति होती है जिसके जरिये पूंजी का वितरण भेदभाव से रहित होना चाहिये। उसका पैमाना इस आधार पर नहीं होना चाहिये कि कौन से राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार है या सहयोगी दलों की है या फिर विरोधी दलों की है अथवा किससे समर्थन मिलेगा या किससे नहीं मिलेगा। सेन्ट्रल पूल का पैसा अलग–अलग राज्यों से आता है और वह पूरे देश के सम्मिलित पुरुषार्थ का परिणाम होता है। राज्यों की ज़रूरतों के आधार पर वह राज्यों को दिया जाता है। इस पक्षपात से न केवल विरोधी पार्टी की सरकारों वाले प्रदेशों में असंतोष फैलेगा बल्कि केन्द्र के साथ उनकी एकजुटता में भी कमी आयेगी। यह देश की एकता के लिये घातक होगा। इस भेदभावपूर्ण बजट की पहली प्रतिक्रियास्वरूप यह सामने आया है कि 27 जुलाई को आयोजित नीति आयोग की बैठक का चार राज्यों ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के. रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में नहीं जायेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी जायेंगी लेकिन वे सवाल पूछने की तैयारी से जा रही हैं। बजट से राजनैतिक हितों को साधने का खेल संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह इसलिये बहुत घातक है कि यदि इसे परम्परा बना दिया गया तो बजट एक राजनैतिक हथियार बन जायेगा।

राजनैतिक हथियार बनता केन्द्रीय बजट

बुधवार को लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024–25 का बजट जहां एक ओर देश के मु–ी भर लोगों को खुशी और ज्यादातर वर्गों के लिये निराशा लेकर आया है, वैसे ही गिनती के राज्यों को खुश करने वाला जबकि अधिकतर को नाखुश करने वाला साबित हुआ है। सरकार बनाने में मददगार रहे दो राज्यों– बिहार और आंध्रप्रदेश की झोलियों को जिस तरह से केन्द्र सरकार ने भरा है, उससे अनेक राज्यों का मायूस होना स्वाभाविक है। इस बजट में जिस प्रकार से सरकार ने भेदभाव बरता है उससे राज्यों में फूट पड़ने की आशंका है; और उसका सबसे बुरा पहलू यह है कि वह देश की संघीय व्यवस्था पर गहरी चोट है। पिछले 10 वर्षों से देश पर शासन कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य सिपहसालार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अनेक कृत्यों से जिस तरह भारत के संघीय ढांचे की नींव को हिलाकर रख दिया है, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिये। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यदि बजट का इस्तेमाल कर राज्यों का राजनैतिक समर्थन जुटाने की परम्परा चल पड़ी तो केन्द्रीय राजस्व का बंटवारा अलग–अलग राज्यों की ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि सियासी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाने लगेगा। यह व्यवस्था वंचित रह गये राज्यों में असंतोष को जन्म देगा।

उल्लेखनीय है कि आंध्रप्रदेश की तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) के 16 और बिहार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 12 सांसदों (लोकसभा सदस्य) के बल पर मोदी सरकार टिकी हुई है। पहले से ही अंदेशा था कि अपने समर्थन के एवज में इन दोनों ही पार्टियों के नेता, क्रमशः चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार (अपने–अपने राज्यों के मुख्यमंत्री) केंद्र की बांहें मरोड़कर कीमत वसूल करेंगे। इन दोनों नेताओं की अपने–अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग रही है। मांग तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी थी लेकिन वहां अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन गयी है इसलिये वह मसला कम से कम वहां तो खत्म हो गया है। इस बजट में टीडीपी और जेडीयू के प्रति केन्द्र का खास अनुराग झलका है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण 2018 में भाजपा का साथ छोड़कर नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस को टा–टा कर दिया था, इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में फिर से उसका दामन थामा था। तभी से नायडू की मांग थी कि आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य के बन जाने से उन्हें अपनी राजधानी बनाने की ज़रूरत है। इसके लिये 15000 करोड़ रुपये उन्हें दिये गये। उनका खुश होना स्वाभाविक है।

दूसरी खुशी नीतीश बाबू को मिली है। चुनाव के ऐन पहले विपक्षी गठबन्धन इंडिया को छोड़कर एनडीए में 17 महीने बाद वापसी करने वाले नीतीश कुमार को भी पुरस्कार मिला है– 59 हजार करोड़ रुपए का। इसका बड़ा हिस्सा बिहार में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने सम्बन्धी उपायों पर खर्च होंगे। हालांकि इसकी हवा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (सांसद) ने यह कहकर निकाल दी है कि जब तक नेपाल और उप्र से बिहार को जाने वाली नदियों की बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक बिहार की नदियों की बाढ़ को नियंत्रित कर पाना असम्भव है। जिस तरह से चंद्रबाबू अब विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात भूल गये हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी इससे इतने गदगद हैं कि वे पत्रकारों से कह रहे हैं कि, 'वे तो पहले से कह रहे थे कि उन्हें या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज। केन्द्र ने यह राशि तो दे ही दी है।' हालांकि वे भूल रहे हैं कि इससे बड़ी राशि का ऐलान तो मोदी राज्य की अपनी प्रचार सभाओं में करते रहे थे। बहरहाल, यह भी सच है कि यह राशि राज्य द्वारा केन्द्र की देखरेख और निर्देश पर ही खर्च करनी होगी। जो भी हो, यह आवंटन नीतीश को अपना चेहरा छिपाने और इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल होने के फैसले को सही ठहराने के लिये काफी है।

केन्द्रीय बजट एक साझा सम्पत्ति होती है जिसके जरिये पूंजी का वितरण भेदभाव से रहित होना चाहिये। उसका पैमाना इस आधार पर नहीं होना चाहिये कि कौन से राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार है या सहयोगी दलों की है या फिर विरोधी दलों की है अथवा किससे समर्थन मिलेगा या किससे नहीं मिलेगा। सेन्ट्रल पूल का पैसा अलग–अलग राज्यों से आता है और वह पूरे देश के सम्मिलित पुरुषार्थ का परिणाम होता है। राज्यों की ज़रूरतों के आधार पर वह राज्यों को दिया जाता है। इस पक्षपात से न केवल विरोधी पार्टी की सरकारों वाले प्रदेशों में असंतोष फैलेगा बल्कि केन्द्र के साथ उनकी एकजुटता में भी कमी आयेगी। यह देश की एकता के लिये घातक होगा। इस भेदभावपूर्ण बजट की पहली प्रतिक्रियास्वरूप यह सामने आया है कि 27 जुलाई को आयोजित नीति आयोग की बैठक का चार राज्यों ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के. रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में नहीं जायेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी जायेंगी लेकिन वे सवाल पूछने की तैयारी से जा रही हैं। बजट से राजनैतिक हितों को साधने का खेल संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह इसलिये बहुत घातक है कि यदि इसे परम्परा बना दिया गया तो बजट एक राजनैतिक हथियार बन जायेगा।

रजिया सुल्तान से राबड़ी देवी तक एक जैसी कहानी

इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, अभी एक महिला राष्ट्रपति हैं, इससे पहले भी एक महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं। अंतरिक्ष से लेकर सेना, पुलिस, चिकित्सा, न्याय क्षेत्र, पत्रकारिता, उद्योग हर जगह महिलाएं अपनी काबिलियत का लोहा मनवाती रही हैं। लेकिन इस बात का हवाला देकर यह कहना कि देश में महिला सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाओं को अब बराबरी का दर्जा मिलने लगा है, खुद को छलावे में रखने से अधिक और कुछ नहीं है। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो', बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे सदन में राजद विधायक रेखा देवी के लिए ऐसा कहा। इससे पहले कल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सांसद ललन सिंह ने राबड़ी देवी के बारे में कहा कि उन्हें हस्ताक्षर करना तो ढंग से आता नहीं, वो बजट क्या समझेंगी। दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 के बीच शासन करने वाली रजिया सुल्तान के लिए कहा जाता था कि उनमें सारी खूबियां थीं, सिवाए एक के, कि वह महिला थी। हिंदुस्तान 1236 से 2024 में आ गया, लेकिन महिलाओं के लिए हिकारत भरी सोच अब भी वैसी ही है। क्या फर्क पड़ता है कि इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, अभी एक महिला राष्ट्रपति हैं, इससे पहले भी एक महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं। अंतरिक्ष से लेकर सेना, पुलिस, चिकित्सा, न्याय क्षेत्र, पत्रकारिता, उद्योग हर जगह महिलाएं अपनी काबिलियत का लोहा मनवाती रही हैं। लेकिन इस बात का हवाला देकर यह कहना कि देश में महिला सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाओं को अब बराबरी का दर्जा मिलने लगा है, खुद को छलावे में रखने से अधिक और कुछ नहीं है। अगर महिलाएं अपने लिए बनाए दायरों से निकल कर बाहर आ रही हैं और उनके लिए असंभव, अछूते समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, तो इसके पीछे या तो उनकी कोई मजबूरी होती है या परिवार का अभूतपूर्व सहयोग और प्रगतिशील सोच का असर होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि देश में महिलाओं के लिए सोच बदल चुकी है। मानसिकता में अब भी लैंगिक भेदभाव कूट–कूट कर भरा हुआ है, जिसके उदाहरण उपरोक्त बयानों से समझे जा सकते हैं। देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सात बार बजट पेश करके रिकार्ड बना लिया है। उनके बजट का सटीक और तार्किक विश्लेषण करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल होंगी, जिन्हें अर्थशास्त्र की गहरी समझ होगी। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि राबड़ी देवी को इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ललन सिंह के हिसाब से उन्हें हस्ताक्षर करने ठीक से नहीं आते तो वे बजट पर भी नहीं बोल सकती। क्या ललन सिंह नरेन्द्र मोदी के बारे में भी ऐसी ही बात कह सकते हैं, क्योंकि श्री मोदी हस्ताक्षर अच्छे से कर लें, लेकिन अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो वे नहीं हैं। उनकी डिग्री भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, अर्थशास्त्र की नहीं है। फिर भी वे शिक्षकों से लेकर वैज्ञानिकों, बुनकरों से लेकर उद्योगपतियों सबको समझाइश देते रहते हैं। राबड़ी देवी को और देश के तमाम नागरिकों को बजट पर बोलने का उतना ही हक है जितना ललन सिंह या नरेन्द्र मोदी को है। क्योंकि बजट देश के आम नागरिकों के लिए बनता है और उनके ही धन से बनता है, इसलिए अपने विचार रखने का अधिकार भी है। ललन सिंह को अगर राबड़ी देवी के विचारों को खारिज करना ही था तो अपने तर्क सामने रखते। लेकिन उनका पौरुषवादी अहंकार यहां आड़े आ गया कि एक महिला, जो उनके हिसाब से पर्याप्त शिक्षित भी नहीं है और ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री, चार बार की विधायक और विधानपरिषद की सदस्य हैं, वो कैसे बजट पर अपनी राय दे सकती हैं।

कुछ ऐसी ही तकलीफ नीतीश कुमार को भी हो गई, जब राजद विधायक रेखा देवी को उन्होंने केवल इसलिए चुप कराना चाहा, क्योंकि वे एक महिला हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर रेखा देवी अपनी बात रख रही थीं और नीतीश कुमार को बोलने नहीं दे रही थीं, तो गुस्से में आकर नीतीश कुमार ने कहा कि बोल रही हो, फालतू बात। इन लोगों ने किसी महिला को आगे बढ़ाया है क्या? पांचवीं के बाद मैंने महिलाओं को पढ़ाया है। इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भूल गए कि रेखा देवी को मसौढ़ी की जनता ने विधानसभा में इसलिए नहीं भेजा कि वो चुपचाप सरकार की बात सुनती रहें, बल्कि जनता की ओर से आवाज उठाएं इसलिए भेजा है। नीतीश कुमार यहां महिला होने के नाम पर रेखा देवी को चुप कराने लगे और ये भूल गए कि वे खुद जनता की आवाज दबा रहे हैं। अगर जदयू अभी इंडिया गठबंधन का साथी होता तो राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वतः संज्ञान लिए नोटिस नीतीश कुमार और ललन सिंह को पहुंच जाते। लेकिन जदयू के कारण भाजपा की सरकार सत्ता में बनी हुई है, तो एक तरह से जदयू को भी महिलाओं के अपमान की खुली छूट मिल ही गई है। याद कीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाणी और विचार महिलाओं के लिए किस तरह के रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की मुंबई की रैली में शक्ति शब्द का जिक्र भाजपा को घेरने के लिए किया तो नरेन्द्र मोदी ने इसे मातृ शक्ति से जोड़ कर कहा कि मैं आखिरी सांस तक शक्ति के सम्मान के लिए लडूंगा। लेकिन इसी चुनाव में मंगलसूत्र बेचने से लेकर विपक्षी दलों के मुजरा करने की बात कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी नजर में महिलाओं का ओहदा क्या है। सोनिया गांधी के लिए श्री मोदी कांग्रेस की विधवा और सुनंदा पुष्कर के लिए पचास लाख की गर्लफ्रेंड जैसी ओछी टिप्पणी कर ही चुके हैं। प.बंगाल जाकर संदेशखोली की महिलाओं के दर्द का जिक्र करने वाले नरेन्द्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए, न ही वहां की पीड़ित महिलाओं की कोई सुध उन्होंने ली। महिला पहलवानों को भी उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया है कि वे अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ें।

दरअसल नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार, ललन सिंह ये केवल चेहरा और नाम हैं, इनके बयानों और विचारों में समाज की असलियत का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जिसमें ऊपरी तौर पर बात महिला बराबरी और सम्मान की होती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक सड़ी–गली सोच पसरी हुई है, जिसमें महिला को किसी भी हद तक जाकर प्रताड़ित किया जा सकता है। फिर चाहे वह सरेआम निर्वस्त्र कर के जुलूस निकालना हो या जिंदा गाड़ना हो।

सलीम–अनारकली की काल्पनिक कहानी में यह बताया गया है कि शहंशाह अकबर ने हुकूमत की खातिर अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। फिल्म मुगले आजम में इसका प्रभावशाली चित्रण है, फिल्म में दिखाया गया है कि दीवार के दूसरी ओर से अनारकली को निकाल लिया जाता है, यानी यहां अकबर का उदार रूप दिखा दिया गया। फिल्म है, तो उसमें कल्पनाओं का खेल किया जा सकता है। लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने शासन में दो महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश पर क्या कहेंगे, किस तरह अपना उदारवादी चेहरा, लाड़ली बहनों के काबिल भाई का चेहरा प्रस्तुत कर पाएंगे।

रीवा जिले में ममता और आशा पांडेय नाम की दो महिलाओं को जमीन विवाद के कारण दबंगों ने जमीन में जिंदा दफना ही दिया था, क्योंकि इन दोनों देवरानी–जेठानी ने उनकी जमीन से होकर गुजरने वाली सड़क का विरोध किया। घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था और इन दोनों ने विरोध करने का साहस दिखाया तो पुरुषों ने भी अपनी ताकत दोनों को जमीन में गाड़ने में दिखा दी। इस घटना का वीडियो बना और वायरल हुआ तो उन दोनों की जान बचाई गई और अभी उनका इलाज चल रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन में आदिवासी के सिर पर पेशाब करने का शर्मनाक कृत्य सामने आया था तो अपनी छवि बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी को घर बुलाकर उसके पैर धोए। अब मोहन यादव की बारी छवि बचाने की है। क्या इस रक्षा बंधन पर इन दोनों महिलाओं से मुख्यमंत्री राखी बंधवाएंगे और उन्हें रक्षा का वचन देंगे, ये देखना होगा।

अपना बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने बजट पटल बड़े आत्मविश्वास के साथ आईं, जो यह एक प्रतीकात्मक इशारा था कि वह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एक परिवर्तनकारी संघीय बजट के रूप में लोगों द्वारा प्रत्याशित प्रावधानों के साथ आई हैं। अल्पमत के जनादेश के साथ शासन करने की अनिवार्यताओं को दर्शाते हुए एक रणनीतिक पैंतरेबाज़ी में सीतारमण ने एक ऐसा दस्तावेज़ पेश किया जिसे राजनीतिक बजट कहा जा सकता है, एक ऐसा दस्तावेज़ जो आर्थिक प्रबंधन की पारंपरिक अनिवार्यताओं की तुलना में गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के लिए अधिक अनुकूल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने बजट पटल बड़े आत्मविश्वास के साथ आईं, जो यह एक प्रतीकात्मक इशारा था कि वह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एक परिवर्तनकारी संघीय बजट के रूप में लोगों द्वारा प्रत्याशित प्रावधानों के साथ आई हैं। फिर भी, 23 जुलाई को राष्ट्र के सामने जो कुछ सामने आया, वह कोई पारंपरिक आर्थिक खाका नहीं था, बल्कि एक नाजुक गठबंधन बजट था, जिसे अलग–अलग राजनीतिक गठबंधनों को खुश करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था।

अल्पमत के जनादेश के साथ शासन करने की अनिवार्यताओं को दर्शाते हुए एक रणनीतिक पैंतरेबाज़ी में सीतारमण ने एक ऐसा दस्तावेज़ पेश किया जिसे राजनीतिक बजट कहा जा सकता है, एक ऐसा दस्तावेज़ जो आर्थिक प्रबंधन की पारंपरिक अनिवार्यताओं की तुलना में गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के लिए अधिक अनुकूल है। फिर सबसे दुखद बात यह कि उन्हें इस बात पर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि उनके खेल कौशल को बजट बनाने के अन्यथा गंभीर कार्य के लिए स्पष्ट विचलन के रूप में देखा जायेगा। बिहार और आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा समर्थित अल्पमत भाजपा सरकार की पृष्ठभूमि के आलोक में बजट की रूपरेखा में समझौते और समायोजन के अमिट निशान थे, जहां संख्याएं अक्सर सिद्धांतों या विवेक से अधिक नीति निर्धारित करती हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अपेक्षित उपायों की चूक ने व्यापक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को रेखांकित किया– एक चतुर आर्थिक जाल–बट्टा, जो समकालीन भारत में गठबंधन शासन की पेचीदगियों को दर्शाता है। सीतारमण के संबोधन का मुख्यबिंदु रोजगार सृजन पर जोर था, जो एक चिरस्थायी चिंता रही है, जो आर्थिक झटकों से और बढ़ गई है। भाजपा की चुनावी असफलताओं के बाद पार्टी के चुनाव–पश्चात विचार–विमर्श में यह तथ्य सामने आया। फिर भी, सरकार की रोजगार सृजन के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के बावजूद ठोस, लक्ष्य–विशिष्ट प्रस्तावों की अनुपस्थिति स्पष्ट थी। रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत रोडमैप की अनुपस्थिति और अल्प–रोजगार और बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बुलंद बयानबाजी को मूर्त परिणामों में बदलने में सक्षम ठोस उपायों की कमी इतनी स्पष्ट थी कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बजट का विशुद्ध रूप से आर्थिक गणना के बजाय राजनीतिक गणना की ओर झुकाव क्षेत्रीय भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई राजकोषीय प्राथमिकताओं के परस्पर क्रिया द्वारा रेखांकित किया गया था। सत्ता पर भाजपा की कमजोर पकड़ के लिए महत्वपूर्ण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बजटीय विचार–विमर्श में प्रमुखता से उभरे, उनकी रणनीतिक अनिवार्यताएं अक्सर आर्थिक विवेक की सार्वभौमिक मांगों पर भारी पड़ीं। संसाधन आवंटन की रूपरेखा इन क्षेत्रीय क्षत्रपों की छाप को दर्शाती है, जो कि अनियंत्रित आर्थिक प्रबंधन के आदर्शवाद पर गठबंधन शासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के भारी पड़ने को सामने रखती है। समावेशी विकास के प्रति सीतारमण के प्रस्ताव राजनीतिक सुविधा की अनिवार्यताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, फिर भी इस कथित प्रतिबद्धता को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित विरोधाभासों को सामने लाते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ठोस उपायों की अनुपस्थिति– जो कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम आदमी के लिए एक मुख्य डर है– राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच असंगत तालमेल को ही रेखांकित करती है।

शुरू हुई रजिस्ट्री की कार्रवाई, दो दिन में आठ किसानों ने की रजिस्ट्री, 200 से अधिक दे चुके हैं सहमति

मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण नया शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाया जाना है। इसके लिए जद में आए किसानों की जमीन को खरीदा जा रहा है। दो दिन में आठ किसानों ने चार एकड़ भूमि परियोजना के लिए रजिस्ट्री की है इसके लिए जीडीए प्रभावित किसानों को सुकल रेट का चार गुणा दर दे रहा है।

संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की प्राथमिकता वाली नया गोरखपुर परियोजना के लिए जद में आ रहे किसानों से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज हो गई है। दो दिन में आठ किसानों ने चार एकड़ भूमि परियोजना के लिए रजिस्ट्री की है, इसके लिए जीडीए प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा दर दे रहा है। रजिस्ट्री कराने का सिलसिला बालापार गांव से शुरू हुआ है।

नया गोरखपुर बसाने के लिए 158.377 हेक्टेयर जमीन खरीदी

मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण (नया शहर प्रोत्साहन) योजना के तहत 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाया जाना है। इसके लिए पिपराइच रोड के चार गांव मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की 158.377 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। इसके लिए तीन करोड़ 35 लाख 70 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित हुई है। जीडीए ने मुआवजे के लिए शासन से तीन हजार करोड़ की मांग की थी, जिसके सापेक्ष 400 करोड़ रुपये मिल गए हैं। अब जीडीए ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को पहले दिन बालापार गांव के छह और दूसरे दिन मंगलवार को दो किसान जीडीए कार्यालय पहुंच कर जमीन रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया पूरी कराई।

रजिस्ट्री से पहले खाते में पहुंचा पांच करोड़

जमीन रजिस्ट्री से पहले ही किसानों के खाते में कुल रकम करीब पांच करोड़ रुपये जीडीए ने ट्रांसफर कर दिया। बालापार में करीब 62.17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है। पिपराइच रोड पर मानीराम, रहमतनगर, सोनबरसा और बालापार के करीब 158.377 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। नया गोरखपुर के तौर पर किसी परियोजना के लिए जमीन लेने की कार्रवाई जीडीए करीब 20 साल बाद कर रहा है। इससे पूर्व राप्तीनगर विस्तार के लिए वर्ष 2003–5 में आठ राजस्व ग्रामों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी।

ग्राहकों को संतुष्ट रखने पर गोरखपुर एयरपोर्ट को देश में मिला आठवां स्थान

संवाददाता, गोरखपुर। जिले के एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में आठवां स्थान मिला है। देश के अन्य एयरपोर्ट के मुकाबले कम संसाधन में एयरपोर्ट को यह उपलब्धि मिली है। गोरखपुर के साथ ही देहरादून, प्रयागराज जिले को भी अखिल भारतीय स्तर पर आठवीं रैंक मिली है। पहले स्थान पर राजमुंदरी दूसरे स्थान पर गग्गल, तीसरे पर लेह है।

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआई) द्वारा प्रत्येक छह माह में अखिल भारतीय स्तर पर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक जारी किया जाता है। इस दौरान जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसंबर तक की अवधि में सर्वे के आधार पर एएआई अपनी रिपोर्ट जारी करता है।

इस सर्वे में एयरपोर्ट पर ही यात्रियों से वहां मौजूद सुविधाओं के बारे में पूछा जाता है। यात्रियों से लिए गए फीडबैक के आधार पर ही एयरपोर्ट की रैंक निर्धारित की जाती है। इस वर्ष जनवरी से जून तक तक हुए सर्वे की रिपोर्ट अब एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने जारी की है। इसमें केवल घरेलू उड़ान संचालित किए जाने वाले 61 एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं।

आठ शहरों के लिए 16 उड़ान

गोरखपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में एक दिन में आठ शहरों के लिए 16 उड़ान हो रही है। हर दिन यहां 2400–2500 यात्री आ रहे हैं। यहां पर बैठने के लिए एसी हाल, एक्सीलेटर लिफ्ट समेत अन्य सुविधाएं यात्रियों के लिए दी गई हैं। एयरपोर्ट प्रभारी प्रचालन विजय कौशल ने कहा कि एयरपोर्ट को आठवीं रैंक मिली है। कम संसाधन में यहां यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए यात्रियों का फीडबैक हमेशा अच्छा ही मिलता है।

बस्ती में पकड़ा गया कचहरी से फरार हुआ हत्यारोपित रुपये के लिए भाई संग मिलकर की थी पिता की हत्या

सोमवार को कचहरी में पेशी पर आया था भाई का हत्यारोपित सोनू सिंह भागने के बाद बस्ती जिले के रुधौली क्षेत्र में रहने वाली बहन के घर पहुंचा था

संवाददाता,गोरखपुर। कचहरी लाकअप से सोमवार को फरार हुए भाई के हत्यारोपित को कैंट थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह बस्ती जिले में बहन के घर से दबोच लिया। फरार होने के बाद बस व आटो से वह बहन के घर पहुंचा था। कैंट थाना पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है।

सिकरीगंज के बारीगांव में रहने वाले सोनू सिंह ने आठ जनवरी 2021 को रुपये के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर चचेरे भाई उमेश सिंह की मदद से अपने बड़े भाई बालेंद्र सिंह की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस मामले में सिकरीगंज थाना पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को जेल भेजा था।

इस मामले में आठ मई 2022 को तत्कालीन थानेदार दीपक सिंह ने सोनू व देवेंद्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई जबकि सोनू जेल में ही था। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट नंबर चार में दोनों की पेशी थी। देवेंद्र कोर्ट में पहुंचा था।

जेल से पेशी पर आया सोनू लाकअप से कोर्ट जाने के लिए निकला तो रास्ते में सिपाही राजरतन को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने सिपाही को निलंबित कर दिया। देर रात लाकअप प्रभारी ने इस मामले में सिपाही राजरतन व फरार हुए बदमाश सोनू सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कचहरी से फरार होने के बाद सोनू बस्ती जिले के रुधौली थानाक्षेत्र स्थित सुरवार खुर्द गांव में रहने वाली बहन के घर गया था।तलाश में जुटी कैंट थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन पर संकट एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

गोरखपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला गैस योजना के एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर संकट मंडरा रहा है। इन कनेक्शन पर सिर्फ एक उपभोक्ता यानी महिला मुखिया का ही नाम दर्ज है। नियमानुसार राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधारकार्ड का नंबर कनेक्शन पर दर्ज होना चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि परिवार में दूसरा कनेक्शन तो नहीं है। अब तेल कंपनियों ने ऐसे कनेक्शनों पर परिवार के अन्य सदस्यों का भी आधारकार्ड नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सभी वितरकों को उपभोक्ताओं की सूची भी दे दी गई है।

गरीब परिवारों की सुविधा को शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इसके तहत घर की महिला मुखिया के नाम से कनेक्शन जारी किया गया था। कनेक्शन लेने वाली महिलाओं को रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की यह राशि महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है। कनेक्शन लेते समय महिला मुखिया के साथ ही राशनकार्ड पर दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का आधारकार्ड भी लगाना होता है लेकिन गोरखपुर क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के स्वजन का आधारकार्ड नहीं दर्ज किया गया है।

हिस्ट्रीशटर ने साथी संग की थी एडिशनल सीएमओ से लूट

सीसीटीवी से खुला राज, हो गया गिरफ्तार

संवाददाता,गोरखपुर। हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथी संग सिद्धार्थनगर के एडिशनल सीएमओ डॉ. राजकिशोर शर्मा से लूट दिनदहाड़े लूट की थी। सीसी कैमरा फुटेज की मदद से कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह हिस्ट्रीशीटर व उसके साथी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का मोबाइल फोन व 1050 रुपये बरामद किए। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शाहमारूफ मोहल्ले में रहने वाले डा. राजकिशोर शर्मा सिद्धार्थनगर जिले में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एडिशनल सीएमओ) के पद पर तैनात हैं। शनिवार को अपराह्न तीन बजे वह जिला अस्पताल जा रहे थे। कोतवाली क्षेत्र में तुरहा चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बाइक रोकते ही बदमाश उनका मोबाइल फोन छीनने लगे। विरोध करने पर धक्का देकर नाली में गिराने के बाद मारपीट कर जेब में रखे 6750 रुपये व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। एडिशनल सीएमओ की शिकायत पर लूट व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। घटनास्थल के पास लगे सीसी कैमरे का फुटेज देखने पर पता चला कि खूनीपुर में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर ईशान उर्फ जीशान ने अपने साथी छोटेकाजीपुर के मोहम्मद नातिक के साथ मिलकर वारदात की थी। ईशान पर 14 व नातिक पर दो मुकदमे दर्ज हैं।दोपहर बाद बदमाशों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

गोरखपुर में नाबालिग छात्राओं की ड्रेस नाप रहा था एजाज

सहजनवां के सरकारी विद्यालय में कक्षा छह की छात्राओं को कराया जाना है निशुल्क ड्रेस का वितरण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से की शिकायत, महिला शिक्षक लगाई गईं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां छात्राओं की ड्रेस नाप रहे युवक को देख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क गए। पूछताछ करने पर नाप लेने वाले शख्स ने अपना नाम बताया तो मामला और बिगड़ गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि छात्राओं की नाप लेने के लिए महिला टेलर को क्यों नहीं बुलाया गया ?

संवाददाता, गोरखपुर। सहजनवां में छात्राओं की ड्रेस नाप रहे युवक को देख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता भड़क गए। कक्षा की छह में पढ़ने वाली 14 से 16 वर्ष की छात्राओं को असहज स्थिति में देखकर उन्होंने महिला टेलर बुलाने की मांग की।

स्कूल प्रबंधन ने मामला बिगड़ता देख आनन–फानन में महिला शिक्षक को इस काम में लगाया। एसडीएम ने प्रधानाचार्य से बात कर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है।

सहजनवां तहसील में कक्षा छह से 12 तक सरकारी विद्यालय संचालित है। वर्तमान में यहां 161 छात्राओं का नामांकन है। वर्तमान सत्र में शिक्षण कार्य शुरू होने के साथ छात्राओं को निशुल्क ड्रेस वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विभाग ने इसके लिए टेंडर कर दिया है।

ड्रेस के लिए छात्राओं का नाप होना था। संबंधित ठीकेदार ने इसके लिए पुरुष टेलर बुला लिया। एजाज अहमद नाम का व्यक्ति स्कूल में पहुंचकर छात्राओं की नाप लेने लगा। युवक द्वारा ड्रेस की नाप लेने से छात्राएं असहज महसूस कर रही थीं। इसकी जानकारी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मिली तो रंजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। पुरुष टेलर को तत्काल नाप लेने से रोकते हुए उन्होंने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वह तो कर्मचारी है। सज्जाद के बुलाने पर वह यहां आया था। छात्राओं की नाप लेने के लिए महिला टेलर को क्यों नहीं बुलाया गया, इस सवाल पर उसने गलती स्वीकार की। प्रधानाचार्य की गैर मौजूदगी के कारण कार्यकर्ताओं ने उप प्रधानाचार्य से मिल कर आपत्ति जताई। उन्होंने तत्काल महिला शिक्षिका को नाप लेने के लिए लगा दिया। स्कूल से निकलने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता अभिषेक त्रिपाठी, अरुण सिंह विक्की, आदित्य कुमार आदि एसडीएम से मिलने तहसील पहुंचे और उनसे मुलाकात कर इस पर आपत्ति जताई। एसडीएम ने प्रधानाचार्य को फोन कर दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिए।

सहजनवां एसडीएम दीपक गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुरुष टेलर द्वारा छात्राओं की नाप लेने के संबंध में शिकायत की थी। प्रधानाचार्य को संबंधित कर्मी को स्पष्टीकरण जारी करने के आदेश दिए गए है।

एएमयू में गोलीबारी: शूटरों को दी गई थी भाइयों की हत्या की सुपारी...इस वजह से शुरू हुई थी दोनों गुटों में रंजिश

अलीगढ़,संवाददाता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार सुबह ठीक 9–16 पर एएमयूकर्मी दो सगे भाइयों पर भाड़े के शूटरों ने फायरिंग कर दी। मेडिकल कॉलोनी के पास हुई सनसनीखेज वारदात में दोनों भाई गोली लगने से जख्मी हो गए। जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एएमयू सुरक्षाकर्मियों ने दो हमलावर मौके से ही दबोचकर पुलिस को सौंप दिए। जबकि एक फरार हो गया है।

इस घटना के मूल में भाई की हत्या के बदले हत्या के इरादे से हमला कराया जाना उजागर हुआ है। मूल रूप से जवां निवासी सगे भाई नदीम महमूद व कलीम महमूद एएमयू रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत हैं। दो माह पहले ही वे रंजिश के चलते गांव छोड़कर यहां मेडिकल कॉलोनी में आकर बसे हैं। एएमयू प्रशासन के मुताबिक रोजाना की तरह सुबह नौ बजे दोनों भाई घर से स्कूटी पर ड्यूटी के लिए निकले। कलीम स्कूटी चला रहा था, जबकि नदीम पीछे बैठा हुआ था।

जैसे ही वे मेडिकल कॉलोनी से कुछ आगे कैंपस में मिंटोई चौराहे पर पहुंचे। तभी पहले से घात लगाए खड़े बाइक सवार हमलावरों ने दोनों पर फायरिंग कर दी। हालांकि निशाना नदीम को बनाया गया। पीछे से चली एक गोली नदीम की कमर के रास्ते पेट में घुस गई। वहीं दूसरी गोली कलीम के सिर को जख्मी करते हुए निकल गई।

एकाएक तीन–चार राउंड फायर होने से कैंपस में भ्रमण कर रहे एएमयू सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए। इस पर हमलावरों ने भागना उचित समझा। मगर घेराबंदी कर मौके से कुछ दूरी पर ही दो आरोपी पकड़ लिए गए। आनन–फानन दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

परिवार की बेटी से रिश्तों को लेकर शुरू हुई थी दोनों पक्षों में रंजिश

अलीगढ़ के जवां कस्बे के नदीम और नगला मल्लाह जीवनगढ़ के तालिब परिवार की रंजिश के मूल में परिवार की बेटी है, जिससे रिश्तों को लेकर उपजी रंजिश में तालिब के सिर पर भाई की हत्या का बदला लेने का ऐसा खून सवार हुआ कि उसने शूटरों को सुपारी दी थी। मौके पर पकड़े गए जाकिर नगर के रहीम व जुबैर ने स्वीकारा है कि उन्हें तालिब ने हत्या की सुपारी दी थी।

उनकी तालिब से कहां मुलाकात हुई। कितने रुपये तय हुए। इस विषय में देर रात तक पूछताछ जारी थी। बताते हैं कि तालिब ने दूसरी बार हमला कराया। इस हमले में भी वही शूटर थे, जो पहले थे। इस बार भी निशाना नदीम था, मगर कई राउंड फायरिंग में गोली छोटे भाई को भी लगी है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी तालिब सहित अन्य को तलाश रही है।

चार वर्ष पहले हुई थी रंजिश की शुरुआत

पुलिस जांच में उजागर हुआ कि हमले में जख्मी नदीम व उसका भाई मूल रूप से जवां के रहने वाले हैं। इनके परिवार की किशोरी के संबंध नगला मल्लाह जीवनगढ़ के गालिब से थे। इस रिश्ते के विरोध में परिवार था। परिवार ने गालिब आदि पर पॉक्सो की धारा में तीन वर्ष पहले जवां में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद किशोरी के दूसरे युवक अयाज से संबंध हो गए। इस पर गालिब ने गुस्से में अयाज का सिर मुंडवा दिया।

इस घटनाक्रम के बाद अयाज और किशोरी ने योजना बनाकर डेढ़ वर्ष पहले गालिब को बातों में उलझाकर बुलाया और छेरत के पास उसकी हत्या कर शव खेतों में फेंक दिया। इस हत्या का मुकदमा गालिब के भाई तालिब ने किशोरी, उसके प्रेमी व नदीम पर कराया।

इस मामले में पुलिस ने अयाज व किशोरी को जेल भेजा, जबकि नदीम घटना के समय एएमयू में होने के नाते बच गया। तभी से तालिब नदीम के पीछे लगा था। सितंबर में नदीम पर जवां में हमला हुआ। उस हमले में तालिब व शूटर रहीम आदि जेल गए। तब से वह जमानत पर है।

स्थान बदलते ही जवां से हटी सुरक्षा

नदीम पर हमले के बाद जवां पुलिस ने उसे सुरक्षा दे रखी थी। दो माह पहले नदीम व उसका परिवार वहां से मकान छोड़कर मेडिकल कॉलोनी आ गए। इस पर जवां पुलिस ने सुरक्षा हटा दी। बाद में नदीम ने एएमयू प्रॉक्टर कार्यालय में सुरक्षा की अर्जी दी थी। एएमयू प्रशासन ने उसे नजरंदाज कर दिया। हालांकि तब से दोनों भाई एक साथ ड्यूटी जाते थे। मगर अब मौका पाकर फिर हमला हुआ।

आरोपी मकान बेचकर हुआ गायब

इस घटना के बाद जब तालिब को पुलिस ने तलाशना शुरू किया तो उजागर हुआ कि वह अपना मकान बेचकर काफी पहले जा चुका है। कहां गया है, इसकी जानकारी नहीं है। मगर उसकी पत्नी का नंबर पुलिस को मिला। सर्विलांस की मदद से भी दोनों का सुराग नहीं मिल पा रहा है।

कैंप में घटना, बाहरियों की आवाजाही पर सवाल

इस घटना की खबर पर एएमयू कुलपति प्रो. नईमा गुलरेज आदि मौके पर पहुंच गए। घायलों का भी हाल जाना। मगर एक बार फिर कैंपस में बाहरी अपराधियों की आवाजाही पर सवाल हो रहे हैं। वह तो गनीमत है कि सुरक्षा टीम सक्रिय थी और घेराबंदी कर दो लोगों को दबोच लिया। अगर न पकड़े जाते तो शायद पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मारती रहती। तालिब से पुरानी रंजिश है। इसी रंजिश में मुकदमे चल रहे हैं। इसी क्रम में वह हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। पूर्व में भी आरोपी द्वारा हमला किया गया है। उसी क्रम में यह हमला हुआ है। हमारे परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। कई बार अधिकारियों से कहा गया है। मगर सुनवाई नहीं हुई।–समीना, नदीम की पत्नी

संपत्ति के लालच में 'मास्टरमाइंड' पौत्री ने ही करवाई थी रिटायर्ड रेलकर्मी की हत्या, यूं हुआ खुलासा

लखनऊ,संवाददाता। गोंडा में रिटायर्ड रेलकर्मी की हत्या उसकी पौत्री ने ही संपत्ति के लालच में करवाई थी। मामले में आरोपी पौत्री सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोंडा जिले की कोतवाली मनकापुर क्षेत्र के भरहूं गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलकर्मी पाटेश्वरी चौहान की हत्या संपत्ति के लालच में उनकी पौत्री ने ही कराई थी। मास्टरमाइंड पौत्री ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने दादा की हत्या की साजिश रची थी। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पौत्री समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है जबकि एक अन्य आरोपी फरार है।

पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर ग्रंट गांव के रहने वाले पाटेश्वरी चौहान (80) वर्ष 2007 में रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भरहूं गांव में मकान बनवाकर अकेले ही रहते थे। 19 जुलाई की देर रात घर के बरामदे में सोते समय उनकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उनकी पौत्र वधू सरस्वती देवी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

एसपी के मुताबिक हत्या की तफ्तीश के दौरान पता चला कि पाटेश्वरी की पौत्री रिया उर्फ रिंका चौहान हत्या से पहले 18 जुलाई को फ्लाइट से पुणे चली गई थी। संदेह होने पर रिंका से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि वह अपनी मां के संग मिलकर डेढ़ साल तक बाबा की सेवा करती रही। मगर बाबा पाटेश्वरी अपनी पूरी संपत्ति 17 बीघा जमीन व भरहूं गांव में स्थित मकान बड़ी पौत्र वधू सरस्वती के नाम करना चाहते थे, दो बीघा जमीन सरस्वती के नाम बैनामा भी कर चुके थे। शेष बची 15 बीघा जमीन व मकान भी सरस्वती के नाम करने की बात कह रहे थे। यही वजह रही कि उसने बाबा को रास्ते से हटाने की अपने दोस्त दिनेश चौहान के साथ मिलकर योजना बनाई। मनकापुर के अंबरपुर के रहने वाले सलमान व बंदरहा गांव निवासी अखिलेश उपाध्याय जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। उन्हें अयोध्या में दुकान कराने का लालच देकर शामिल कर लिया। दोनों हत्या को अंजाम देने को तैयार हो गए तो किसी को शक न हो इसलिए वह 18 जुलाई को फ्लाइट से पुणे चली गई। 19 जुलाई की रात दिनेश बाइक से सलमान व अखिलेश को लेकर बाबा के घर पर छोड़कर चला गया। अखिलेश ने बाबा का पैर जकड़ लिया और सलमान ने गला घोंटने का प्रयास किया। मगर वह खुद को बचाने के लिए प्रयास करते रहे।

प्रेमी के घर पहुंची युवती ने खाया कीटनाशक

शादी से इंकार करने पर उठाया ये कदम

गोरखपुर। गोरखपुर गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने बुधवार को प्रेमी के घर पहुंचकर कीटनाशक खा लिया। हालत गंभीर होने पर पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उधर युवती के पहुंचने पर प्रेमी घर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्षेत्र के एक गांव की युवती का पड़ोस के गांव के युवक से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती युवक पर शादी करने का दबाव बना रही थी। लेकिन घर वालों के इनकार करने पर युवक ने भी शादी करने से मना कर दिया।

इधर, जानकारी होने पर युवती के घर वालों ने भी प्रेम प्रसंग को लेकर उसे डांट फटकार लगा दी। इससे नाराज होकर युवती अपने घर से निकली और प्रेमी युवक के घर पहुंच गई। वहां पर युवक को नहीं पाकर उसके दरवाजे पर कीटनाशक खा लिया और कुछ देर बाद अचेत होकर गिर गई। युवक के घर वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया कि युवती का उपचार चल रहा है। गुलरिहा पुलिस को अभी किसी तरफ से तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुबह ईंट हटाने को लेकर बैठी पंचायत

शाम को सरिया–सब्बल से पीटकर हत्या, 12 लोगों पर केस दर्ज

गोरखपुर। राधा देवी की पैतृक जमीन में विपक्षी विश्वनाथ और फूलचंद की दीवार बारिश में गिर गई थी। उसी ईंट को हटाने के लिए उसके पति कई बार कहे। यहां तक कि कई बार पंचायत भी हुआ। मंगलवार सुबह भी दोनों पक्षों के बीच पंचायतन ईंट को हटा लेने की बात हुई। शाम को गिरोहबंद होकर आए सभी आरोपियों ने पति पर हमला कर उनकी हत्या कर दी।

थानाक्षेत्र के पड़ियाडीह गांव में भूमि विवाद को लेकर मंगलवार को हुए घमासान में पुलिस ने 10 नामजद व दो अज्ञात पर हत्या व बीएनएस की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के परिवार के लोगों का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से यह हत्या की गई है। मृतक की पत्नी राधा देवी ने तहरीर में बताया है कि उसकी पैतृक जमीन में विपक्षी विश्वनाथ और फूलचंद की दीवार बारिश में गिर गई थी। उसी ईंट को हटाने के लिए उसके पति कई बार कहे। यहां तक कि कई बार पंचायत भी हुआ। दोनों पक्षों के बीच पंचायतन ईंट को हटा लेने की बात हुई। इसके बावजूद विपक्षियों ने नहीं हटाया। बाद में वह स्वयं उसके दिवंगत पति राजेन्द्र बेटी साधना माधुरी और बेटा गोविन्द ईंट को हटाने लगे। इसी दौरान विपक्षी कन्हैया तिवारी उर्फ रवीन्द्र नाथ निवासी शंकरपुर थाना परशुरामपुर और गांव के ही रामचन्द्र के ललकारने पर विश्वनाथ, फूलचंद्र, संदीप, इन्द्रेश, कौशलेंद्र, आदित्य,आयूष, विद्यावती और दो अज्ञात सरिया, डंडा, भाला व सब्बल हाथों में लेकर आये और मुझे मेरे पति राजेन्द्र,बेटी साधना माधुरी बेटे हरीश व गोविन्द को एकजुट होकर जान से मार डालने की नियत से मारने पीटने लगे। जिससे सभी को चोटें आयीं। उसके पति राजेन्द्र को सब्बल सरिया से सिर पर मार दिया। उन्हें मरा समझकर वह लोग मौके से भाग गये। आनन–फानन में पति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परशुरामपुर पहुंचाया गया। जहां डाक्टर ने जिला चिकित्सालय अयोध्या रिफर कर दिया । अयोध्या में डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष रामफल चौरसिया ने बताया है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

अनूसूचित जाति के छात्र से फीस के लिए अभद्रता

एससी–एसटी आयोग नाराज, तलब की रिपोर्ट

लखनऊ। बीएड कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र से फीस के लिए अभद्रता करने के मामले को एससी–एसटी आयोग ने गंभीरता से लिया है। मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। लखनऊ–गाजियाबाद के ज्ञानस्थली विद्यापीठ के प्रबंधक द्वारा छात्र से जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करने के मामले को अनुसूचित जाति/जनजानति आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष एवं गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने पुलिस आयुक्त गाजियाबाद से बात कर प्रकरण की जानकारी ली और एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में भेदभाव पूर्ण बर्ताव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कॉलेज के चेयरमैन हरिओम शर्मा पर आरोप लगा है कि उन्होंने बीएड कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र से फीस के लिए अभद्रता की। इसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले में प्रबंधक हरिओम शर्मा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि छात्र की हर संभव मदद की जाएगी। सरकार हर युवा को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में किसी शिक्षण संस्थान द्वारा इस तरह की हरकत करना निंदनीय है। इसकी जांच कराई जा रही है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साहब! छोटे भाई ने कागज में मुझे मार डाला

साहब! मैं कमाने बाहर गया तो छोटे भाई ने संपत्ति हड़पने के लिए कागज में मुझे मृत घोषित करा दिया। मृत घोषित कराकर मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब मैं दर–दर भटकने को मजबूर हूं। साहब! मेरे साथ न्याय कीजिए।

गोरखपुर। यह फरियाद लेकर महाराजगंज जिले के बेलवा खुर्द निवासी राकेश गुप्ता (42) खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के पास दौड़ लगा रहे हैं। अधिकारियों के दफ्तरों से निराश राकेश ने अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अर्जी लगाई है। राकेश ने दस साल तक लुधियाना में काम किया। वहां से लौटे तो मां–बाप की मौत हो चुकी थी। आरोप है कि छोटे भाई ने उस्तादी दिखाते हुए राकेश को भी परिवार रजिस्टर में मृत घोषित करा दिया और सारी संपत्ति पर खुद काबिज हो गया। जब राकेश घर पहुंचे तो छोटे भाई ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया।

इसके बाद से ही राकेश शाहपुर इलाके में संगम चौराहा स्थित मानस विहार कॉलोनी के पास एक झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर पत्नी और तीन बच्चों का पेट पाल रहे हैं। काम से छुट्टी मिलने पर वह हाथ में फाइलों का ढेर लेकर खुद को जिंदा साबित करने के लिए महराजगंज और गोरखपुर में प्रशासनिक दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। राकेश ने बताया कि वर्ष 1997 में 15 साल की उम्र में वह लुधियाना कमाने चला गए थे। तब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन गवना नहीं हुआ। तीन साल बाद गांव लौटा, तब गवना हुआ।

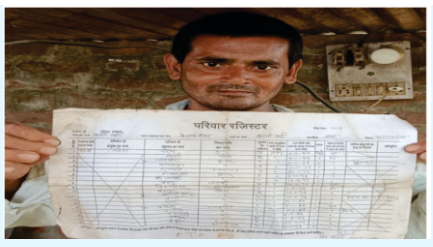

राकेश ने दस साल तक लुधियाना में काम किया। वहां से लौटे तो मां–बाप की मौत हो चुकी थी। आरोप है कि छोटे भाई ने उस्तादी दिखाते हुए राकेश को भी परिवार रजिस्टर में मृत घोषित करा दिया और सारी संपत्ति पर खुद काबिज हो गया। जब राकेश घर पहुंचे तो छोटे भाई ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया।

इसके बाद फिर परिवार के साथ लुधियाना चले गए। वहां से वह हर महीने पांच हजार रुपये घर भेजते रहे। दस साल बाद वह गांव लौटे तो मां–बाप की मौत हो चुकी थी। भाई ने पहचानने से इंकार करते हुए घर से निकाल दिया। दौड़–भाग करके गांव के लोगों के सहयोग से घुघली ब्लॉक से परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाई। रजिस्टर में उन्हें पांच मार्च 1984 में ही मृत घोषित कर दिया गया था। राकेश को मृत घोषित कराकर छोटे भाई ने खेत, घर और दो–दो जगहों पर पूर्वजों की जमीन पर कब्जा कर लिया। 18 जून को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में प्रार्थना दिया। इसके बाद वीडियो और लेखपाल ने गांव जाकर जांच भी की, लेकिन अब भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।

होमगार्ड मामा भिजवा चुका है जेल

राकेश ने बताया कि उसके मामा होमगार्ड हैं। आरोप है कि वह छोटे भाई का सहयोग करते हैं। उन्होंने छोटे भाई के साथ मिलकर दो साल पहले धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें जेल भी भिजवा दिया था। छह महीने बाद जेल से छूटे। राकेश का कहना है कि गांव के लोग उनके साथ हैं। सरकारी दफ्तर से जांच शुरू होती है तो छोटा भाई रुपये खर्च कर रिपोर्ट अपने पक्ष में लगवा लेता है।

सीएम योगी का लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन जारी

सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी ने की कार्रवा
संभागीय निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित, एआरटीओ पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवा
चित्रकूट में समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण स्कूली वाहन को किया गया था सीज
पुलिस लाइन में दो घंटे तक वाहन में बैठे रहे बच्चे, मामला संज्ञान में आते ही लिया गया एक्शन

यूपी की योगी सरकार ने चित्रकूट में स्कूली बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही पर एक्शन लिया है। जिले के संभागीय निरीक्षक द्धप्राविधिकऋ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्धप्रवर्तनऋ के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कूमयों पर सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

संवाददाता, लखनऊ। सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी का एक्शन जारी है। ताजा घटनाक्रम में योगी सरकार ने जनपद चित्रकूट के अंतर्गत स्कूली बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही पर एक्शन लेते हुए जिले के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

बता दें कि सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की हीलाहवाली न की जाए। खासतौर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

2 घंटे तक पुलिस लाइन में खड़ी रही थी बसें

दरअसल, मंगलवार 23 जुलाई को जनपद चित्रकूट के श्रीजी इंटर कॉलेज, खोह के छोटे–छोटे बच्चों को लेकर आ रही दो बसों को वाहन की फिटनेस समाप्त हो जाने के कारण सहायक संभागीय परिहन अधिकारी (प्रवर्तन) चित्रकूट की टीम द्वारा सीज कर बच्चों सहित 10 किमी दूर पुलिस लाइन ले जाया गया था। वाहन को 11:15 बजे सीज कर फायर सर्विस परिसर पुलिस लाइन में दाखिल किया गया व 13:05 बजे छोड़ा गया।

इसके चलते करीब दो घंटे तक बस को खड़ा रखा गया। जानकारी के अनुसार, चित्रकूट जनपद के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) गुलाब चंद्र को संबंधित स्कूलों में जाकर स्कूली बसों के फिटनेस चेक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई, जिसके कारण दोनों वाहनों का फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी नहीं हो पाया। ऐसे में वाहनों को सीज करना पड़ा, जिससे बच्चों को भी तकलीफ हुई।

मामला संज्ञान में आते ही हुआ एक्शन

बुधवार को मामला संज्ञान में आने के बाद योगी सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इसके तहत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) गुलाब चंद्र को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विवेक कुमार शुक्ला के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। साथ ही, प्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़े समस्त कर्मियों को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

ऋतिक हत्याकांड में दो दारोगा और एक सिपाही सस्पेंड

घटना की सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे थे बीट के पुलिसकर्मी
बंथरा गांव में बिजली बनाने को लेकर हुई थी युवक की हत्या, पीएसी बल तैनात

लखनऊ। बंथरा गांव में हुए हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले बीट के दो दारोगा सुभाष यादव, सुशील यादव और सिपाही यत्येंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच एसीपी कृष्णानगर कर रहे हैं। डीसीपी दक्षिणी तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि एसीपी की जो भी रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आरोपितों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी गई है।

डीसीपी ने बताया कि बीट इंचार्ज दारोगा सुभाष यादव, दारोगा सुशील यादव और सिपाही यत्येंद्र सिंह को निलंबित किया गया है। जांच में सामने आया कि विवाद की सूचना मिलने के बाद भी बीट इंचार्ज मौके पर नहीं पहुंचे थे। न ही उनके साथ मौजूद दारोगा सुशील और सिपाही यत्येंद्र गए थे। यही नहीं घटना की जानकारी होने के बाद भी दूसरे दिन जीडी में इंट्री कर बीट इंचार्ज सुभाष यादव गुमशुदा महिला की तलाश में दूसरे जनपद रवाना हो गए। ऐसे में सभी को निलंबित कर एसीपी मोहनलालगंज को जांच दी गई है। एसीपी कृष्णानगर विनय द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। गांव के कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।

गांव में तैनात की गई पीएसी

लखनऊ के बंथरा में बिजली बनाने को लेकर प्रत्यूष सिंह चौहान और ऋतिक पांडेय के बीच विवाद हो गया था। प्रत्यूश ने साथियों के साथ ऋतिक के घर में घुसकर सभी की पिटाई कर दी थी। घटना में ऋतिक की मौत हो गई। हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले बीट के दो दारोगा सुभाष यादव सुशील यादव और सिपाही यत्येंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

हत्याकांड के बाद से दोनों गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस के साथ–साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। यही नहीं ऋतिक के शव गांव से निकला तो दोनों गांव में सन्नाटा पसर गया था। शुक्लागंज गंगाघाट में ऋतिक का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस भी साथ में मौजूद रही।

मास्टर माइड राजीव नयन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

जमानत याचिका मंजूर

प्रयागराज। आरओ एआरओ पेपर लीक के मास्टर माइड राजीव नयन की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक दिन पहले कौशाम्बी पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है। उसे जमानत तो जरूर मिल गई है, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ–एआरओ पेपर लीक मामले के मास्टर माइड राजीव नयन मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

आरओ–एआरओ पेपर लीक के मास्टर माइंड राजीवन नयन को बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। राजीव नयन यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का भी मास्टरमाइंड रहा है। उसे प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

दो मार्च को यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने आरओ–एआरओ पेपर लीक मामले में प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में राजीव नयन मिश्रा का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। 11 फरवरी को आरओ–एआरओ परीक्षा आयोजित की गई थी। राजीव नयन मिश्रा को मेरठ, नोएडा और कौशांबी में दर्ज मामलों में पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं कौशांबी पुलिस ने आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा समेत 23 सदस्यों पर गैंगस्टर लगा दिया है।

कौशाम्बी पुलिस ने मंझनपुर, कोखराज व प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत ने उसे जमानत दी है।

बिजली संकट को लेकर गरमाई राजनीति

कांग्रेस ने घेरा कानपुर केस्को मुख्यालय

केस्को मुख्यालय पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन
बिजली कटौती को लेकर सरकार से रखी मांगे

कानपुर में बिजली संकट को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने केस्को मुख्यालय घेरकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार से बिजली को लेकर कई मांगें भी की हैं। हर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि शहर में इन दिनों रोज बिजली कटौती हो रही है। इसे लेकर जनता में नाराजगी है।

,संवाददाता, कानपुर। शहर में बिजली संकट को लेकर राजनीति गरम है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने बुधवार को केस्को मुख्यालय घेरकर नारेबाजी की। दोपहर 12 बजे से कांग्रेसी सिविल लाइंस स्थित केस्को मुख्यालय के बाहर बैठ गए और नारेबाजी की। केस्को मुख्यालय के बाहर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि शहर में इन दिनों रोज बिजली कटौती हो रही है। इसे लेकर जनता में नाराजगी है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर गए हैं।

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक सोहिल अख्तर अंसारी, दिलीप शुक्ला, पवन गुप्ता, मोहित दीक्षित, युवक कांग्रेस के गौरव पांडेय ने कहा कि केस्को अविलंब सुधार करे, वरना सड़क पर उतरेंगे।

कांग्रेसियों ने दिया ज्ञापन

पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्र ने कहा कि अब जनता के लिए काम करेंगे। इसके बाद कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। उधर, कांग्रेस के पुराने नेताओं ने शहर अध्यक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। इसलिए प्रदर्शन में वो नहीं पहुंचे। इससे गुटबाजी साफ झलकी। पार्टी को नुकसान होना तय है।

अघोषित बिजली कटौती बंद हो, जर्जर व पुराने ट्रांसफार्मर बदलें।

बिजली के गलत बिल व अधिक रीडिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो।

नए आवेदकों के लिए कनेक्शन देने की समयावधि निर्धारित हो।

सबस्टेशन पर दलालों का प्रवेश वर्जित हो। मीटर रीडिंग शत–प्रतिशत हो। पारदर्शिता लाएं।

स्मार्ट मीटर के उपभोग का ब्योरा उपभोक्ता को मिले। सिक्योरिटी जमा पर उपभोक्ता को ब्याज दें।

छात्र ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार कर दी जान

इंदिरानगर इस्माइलगंज में बुधवार सुबह हुई घटना
गाजीपुर जनपद के विश्वेश्वरगंज का रहने वाला था

संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर के इस्माइलगंज में बुधवार सुबह चाचा की लाइसेंसी पिस्टल से 18 वर्षीय छात्र प्रत्यूष सिंह ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। वह कई माह से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसका इलाज भी चल रहा था। प्रत्यूष मूल रूप से गाजीपुर जनपद के विश्वेश्वरगंज में रामजानकी मंदिर के पास के रहने वाले थे। पिता शैलेंद्र सिंह व्यवसायी हैं। यहां इस्माइलगंज में चाचा सत्येंद्र सिंह के यहां एक माह से रहकर इलाज करा रहा था। सत्येंद्र ने बताया कि भतीजा दो साल पहले इंटर में फेल हो गया था। उसके बाद से डिप्रेशन में था और नशे का आदी भी हो गया था।

खून से लथपथ हालत में कमरे में पड़ा प्रत्यूष

हालत में कुछ सुधार होने पर वह एक साल पहले अपने बड़े भाई उदित राज सिंह के साथ देहरादून में रहा। वहां रहकर वह पढ़ाई कर रहा था। एक माह पहले उसकी हालत तबीयत फिर बिगड़ गई। इसके बाद उसे यहां ले आए। मनोचिकित्सक से उसका इलाज चल रहा था। मंगलवार रात सभी लोग सो रहे थे। पिस्टल तकिए के नीचे रखी थी। पता नहीं किस समय प्रत्यूष कमरे में आया उसने पिस्टल निकाल ली और अपने कमरे में जाकर गोली मार ली। सुबह सात बजे आंख खुली तो देखा कि प्रत्यूष खून से लथपथ हालत में कमरे में पड़ा था। अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कर रही मामले की जांच

कूलर और फर्राटा पंखा चल रहा था। इसके कारण गोली चलने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। एसीपी गाजीपुर सर्किल विकास जायसवाल के मुताबिक सत्येंद्र यहां ठेकेदारी करते हैं। उन्हीं के साथ में प्रत्यूष रह रहा था। उसने गोली मार कर जान दी है। अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। सत्येंद्र को पिस्टल अलमारी में लॉक करके रखनी चाहिए। उनकी भी लापरवाही प्रकाश में आयी है। पिस्टल के शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

खुद मकान नहीं तोड़ेंगे तो', मजिस्ट्रेट ने पहले चलवाया बुलडोजर

यूपी के बाराबंकी में मजिस्ट्रेट बुलडोजर के साथ पहुंचे। उन्होंने एक मकान के आंशिक भाग को बुलडोजर से तोड़वाने का आदेश दिया । अन्य लोगों को अंतिम चेतावनी दी कि वे स्वयं ही अपना मकान तोड़ लें नहल तो अपने सामने बुलडोजर से तोड़वा देंगे। अब लोगों ने बुधवार तक स्वयं ही मकान को तोड़ने की बात कही है ।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। तहसील नवाबगंज के एसडीएम का कार्यभार ग्रहण करते ही संयुक्त मजिस्ट्रेट आर जगत साईं ने जमुरिया नदी की सफाई का हाल देखा। महारानी लक्ष्मी बाई इंटर कालेज से करीब 100 मीटर दक्षिण कुछ मकान जमुरिया नदी की 20 मीटर परिधि में बने हैं। इन्हें स्वयं तोड़ने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा, लेकिन भवन स्वामी बहानेबाजी करते रहे। ऐसे में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सख्ती दिखाई। एक मकान के आंशिक भाग को बुलडोजर से तोड़वाने का आदेश दिया। अन्य लोगों को अंतिम चेतावनी दी कि वे स्वयं ही बुधवार तक मकान नहीं तोड़ेंगे तो अपने सामने बुलडोजर से तोड़वा देंगे।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि जमुरिया की सफाई व अतिक्रमण हटाने का काम 95 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है। जिन स्थानों पर दिक्कत आ रही थी, वहां भी लगभग समस्या समाप्त हो गई है। लोगों ने बुधवार तक स्वयं ही तोड़ने की बात कही है। जमुरिया की सफाई में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

पालिका ने खपरैल बाजार में फिर तोड़ा अतिक्रमण

एक अन्य मामले में लखीमपुर में मंगलवार को खपरैल बाजार में नगर पालिका ने अतिक्रमण तोड़कर हटाया और निर्देश दिया है कि दो दिन में दुकानदार अपने लोग तोड़ कर अतिक्रमण हटा लें। वहीं दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण हटा लेने के लिए फिर समय मांगा। खपरैल बाजार में 14 दिन बीत जाने पर भी कुछ ही दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है।

मंगलवार को ईओ नगर पालिका संजय कुमार की अगुवाई में टीम ने अतिक्रमण तोड़ा। इस बीच कई दुकानदारों ने फिर एक दिन का समय मांग लिया जिससे आगे का अतिक्रमण नहीं टूट सका। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नगर पालिका टीम ने बाजार में निरीक्षण किया। जिन दुकानों के आगे गंदगी पाई गई उन्हें हिदायत दी गई कि वह कूड़ादान रखें। ऐसे दो दुकानों पर गंदगी देखकर जुर्माना भी किया गया। ईओ संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान व स्वच्छ भारत मिशन अभियान बराबर चलेगा। जो दुकानदार नाली के ऊपर अतिक्रमण किए हैं वह हटा लें अन्यथा एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

लोकसभा में गूंजा अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा

दिल्ली। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों/अफसरों ने गत वर्ष 'पुरानी पेंशन' बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। उस वक्त यह बात साफ हो गई थी कि सरकार, सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 'पुरानी पेंशन' लागू हो, उन्हें 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना जाए, अब यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र में गूंजने लगा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में कहा, अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत झेल रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए। गुरुवार को रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की मांग उठाई। उन्होंने कहा, ये बल देश की सुरक्षा करते हैं, यहां तक कि संसद भवन की रक्षा का दायित्व भी यही बल निभाते हैं। इन्हें 100 दिन का अवकाश मिले। हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर 'राज्य अर्धसैनिक बोर्ड' का गठन हो।

सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, जब भाजपा विपक्ष में रही तो ओपीएस की बात करती रही। यह सरकार अब 11 वां बजट पेश कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन के लिए परेशान हैं। सरकार, ओपीएस की चर्चा ही नहीं कर रही। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा, आप बहुत बड़े राष्ट्र भक्त बनते हैं। सीमा पर जवान शहादत झेल रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए।

लंबे समय से 'पुरानी पेंशन बहाली' की मांग

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कंधों पर न सिर्फ कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सीमा, बंदरगाह व एयरपोर्ट के अलावा संसद भवन की सुरक्षा का दायित्व भी है। इन बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी व असम राइफल शामिल हैं। इन बलों में लंबे समय से 'पुरानी पेंशन बहाली' की मांग की जा रही है। जब देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो उस वक्त कहा गया है कि नई पेंशन स्कीम, 'भारत संघ के सशस्त्र बलों' को छोड़कर, अन्य सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। तब सेना के तीनों अंगों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' मान लिया गया। उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में रखा गया।

तो शूलटग की घटनाओं को रोका जा सकता है

बतौर हुड्डा, अच्छी बात है कि सेना में आज भी पुरानी पेंशन लागू है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अर्धसैनिक बल भी 'भारत संघ के सशस्त्र बल' हैं। ये भी सशस्त्र बलों की परिभाषा में आने चाहिएं। इनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का कार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि इन बलों में सौ दिन का अवकाश सुनिश्चित होगा। इसके जरिए इन बलों में शूटिंग की घटनाओं को रोका जा सकता है। अभी तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हुई है। इन बलों में जवानों को अभी साठ दिन का अवकाश मिल रहा है। सौ दिन का अवकाश सुनिश्चित हो। इनके हितों की रक्षा के लिए सभी प्रदेशों में 'अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड' का गठन हो।

भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि कर्मियों को 'पुरानी पेंशन' देने का कोई विचार नहीं है। सरकार, एनपीएस में संशोधन कर रही है। इस बाबत कर्मचारी संगठनों की राय ली गई है। उससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं, फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए हैं, उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'पुरानी पेंशन' से वंचित किया गया है।

अदालत से जीती लड़ाई को हराने का प्रयास

दिल्ली उच्च न्यायालय भी यह मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीएपीएफ', 'भारत संघ के सशस्त्र बल' हैं। अदालत ने इन बलों में लागू 'एनपीएस' को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही है। यानी सीएपीएफ, पुरानी पेंशन की हकदार है। एलाइंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी एचआर सिंह कहते हैं, ये दुर्भाग्य है कि अदालत से जीती हुई लड़ाई को केंद्र सरकार, हार में बदलने की मंशा रखती है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अगले माह इस केस में जवाब फाइल किया जाएगा। सीएपीएफ में ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी।

सेना, नेवी और वायु सेना ही 'सशस्त्र बल'

केंद्र सरकार, कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती। सीएपीएफ में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। एक जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें 'एनपीएस' में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें एनपीएस दे दिया।

तब सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायु सेना ही 'सशस्त्र बल' हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में भी कहा गया है कि इस बल का गठन 'भारत संघ के सशस्त्र बल' के रूप में हुआ है। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी एक पत्र में घोषित किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल, 'संघ के सशस्त्र बल' हैं।

बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान

सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं।

इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स हैं, वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे। इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा, ये वहीं पर काम करेंगे। सिविल महकमे के कर्मी तो ऐसी शपथ नहीं लेते हैं।

कोर्ट ने माना था 'भारत संघ के सशस्त्र बल'

सीएपीएफ के 11 लाख जवानों/अफसरों ने गत वर्ष 'पुरानी पेंशन' बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। उस वक्त यह बात साफ हो गई थी कि सरकार, सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार, सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स बताती है। अदालत ने इन बलों में लागू 'एनपीएस' को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी।

दूसरे केंद्रीय संगठनों का मिला समर्थन

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू कराने के लिए अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के पदाधिकारियों ने इसका समर्थन किया है। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मियों की एक विशाल रैली आयोजित करने वाले नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी सीएपीएफ में ओपीएस लागू करने की मांग की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने भी सीएपीएफ सहित सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए रैली आयोजित की थी। ऑल इंडिया एनपीएस इम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने भी सीएपीएफ के लिए ओपीएस की मांग का समर्थन किया है।

पिछले दिनों संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार ने सब्जियों के बढ़ती हुई कीमतों की वजह बताई है। सरकार ने बताया है कि पिछले दो वर्षों में खराब मौसम, जलाशयों का गिरते स्तर और फसल नुकसान ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। देश में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे है। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की खुदरा कीमत पिछले एक महीने में 15 फीसदी से 58 फीसदी तक बढ़ गई हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे मानसून के अलावा कई अहम कारण जिम्मेदार माने जा रहे है। हालांकि, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह स्थिति अस्थाई है। आने वाले दिनों में कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन सब्जियों के दाम तेजी से क्यों बढ़ रहे है? इसके पीछे सरकार ने ये वजह बताई है।

पिछले दिनों संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार ने सब्जियों के बढ़ती हुई कीमतों की वजह बताई है। सरकार ने बताया है कि पिछले दो वर्षों में खराब मौसम, जलाशयों का गिरते स्तर और फसल नुकसान ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। इसी वजह से तेजी से खाद्य कीमतों के दाम बढ़ रहे है। खराब मौसम की स्थिति ने सब्जियों और दालों के उत्पादन की संभावनाओं को प्रभावित किया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि, देश में 2023–2024 में खराब मौसम की घटनाओं बहुत ज्यादा हुआ हैं। इससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। इसे अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में घटने जलाशय के स्तर ने भी कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 22 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 6.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 में 7.5 प्रतिशत हो गई।

आर्थिक सर्वे में बताया गया कि, जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र–विशिष्ट फसल पर रोग के कारण भी सब्जियों में सप्लाई में रुकावट आई है। इसी वजह से टमाटर में कीमतों में उछाल आया है। जबकि प्याज की कीमतों में उछाल की वजह पिछले कटाई सीजन में बारिश, बुवाई में देरी, लंबे समय तक सूखा और दूसरे देशों द्वारा व्यापार से जुड़े कदम उठाना है।पिछले दो सालों में प्रतिकूल मौसम की वजह से कम उत्पादन की वजह से दालों, खास तौर पर अरहर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जबकि रबी सीजन में धीमी बुवाई और दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी गड़बड़ी की वजह से उड़द का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

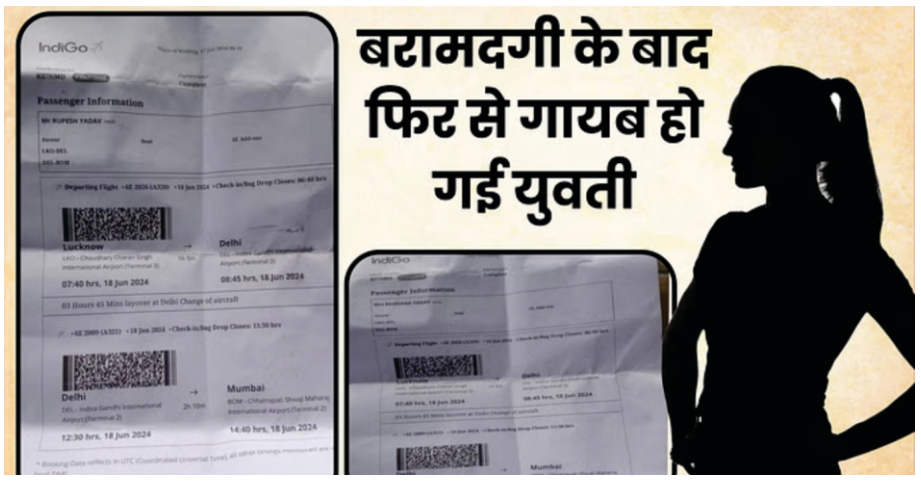

देवरिया। उत्तर प्रदेश के 'खाकी' ने एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। अपहृत किशोरी को बरामद करने के लिए देवरिया पुलिस ने पीड़ित मां से रुपये लिए। मुंबई जाने के लिए मां से ही फ्लाइट के टिकट बुक कराए, इसके बाद वापस लौटने के लिए ट्रेन के टिकट भी मां से ही बुक कराए। देवरिया से गजब का मामला सामने आया है। अपहृत किशोरी की बरामदगी के मुंबई जाने के लिए किशोरी की मां से फ्लाइट का टिकट बुक कराया। इसके अलावा लौटने के लिए भी मां से ट्रेन का टिकट बनवाया था। इसके साथ ही खर्चे के लिए छह हजार रुपये भी लिए थे। तीन पुलिसकर्मी मुंबई से किशोरी को बरामद कर लाए, बरामदगी के बाद युवती फिर से गायब हो गई। अब फिर पीड़ित मां तलाश में थाने का चक्कर काट रही है। दरअसल, देवरिया में कुछ समय पहले गांव का ही एक युवक प्रेम जाल में फंसा कर किशोरी को भगा ले गया। इसकी जानकारी हुई तो मां ने थाने पहुंचकर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसकी लोकेशन मुंबई में मिली।

पुलिस की तीन सदस्यीय टीम उसे मुंबई से लाने के लिए तैयार हुई। स्थानीय पुलिस ने मां से करीब 22,200 रुपये का लखनऊ से फ्लाइट के टिकट बुक कराए। इसके बाद वापसी के लिए करीब सात हजार रुपये के ट्रेन के टिकट भी मां से बनवाए। यही नहीं वहां आने–जाने में होने वाले खर्च के लिए भी पीड़िता की मां से करीब छह हजार रुपये की नगदी भी ली। इसके बाद युवती को बरामद कर मां को सौंप दिया, लेकिन युवती फिर से गायब हो गई। इसके बाद से मां अपनी बेटी की बरामदगी के लिए अब फिर पुलिस से गुहार लगा रही है। बघौचघाट थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली गरीब महिला की बेटी को कुछ दिन पहले गांव का ही एक युवक प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया। मां ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने जांच की तो गायब युवती और युवक की लोकेशन मुंबई में मिली। पुलिस ने महिला को बुलाकर मुंबई जाने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कराने के लिए कहा। पुलिस का कहना था कि जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्द उसे बरामद कर लेंगे। लेट होगा तो वे लोग अपना ठिकाना बदल देंगे। पुलिस कर्मियों ने उक्त असहाय महिला को पूरी तरह झांसे में लेते हुए टिकट बुक कराया। महिला ने एक दरोगा, एक सिपाही और एक महिला कांस्टेबल के मुंबई के टिकट बुक कराए। इसके बाद लौटने के लिए करीब सात हजार के ट्रेन के टिकट बुक कराए। खर्च के लिए उसकी मां से 6000 रुपये भी लिए। महिला ने गांव में कर्ज लेकर किसी तरह से टिकट बनवाए और उनको खर्च के पैसे दिए।

यूपी पुलिस की करतूतः अपहृत किशोरी की बरामदगी के लिए मां से बुक कराया हवाई जहाज का टिकट, ये शर्मनाक काम भी किया

समंदर के पानी में यूं पोज देती नजर आईं रवीना टंडन की बेटी

समंदर किनारे दिया कातिलाना पोज रवीना टंडन की बेटी हैं राशा थडानी अमन देवगन के साथ करेंगी डेब्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रवीना टंडन इन दिनों अपने बच्चों के साथ इटली में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस बीच उनकी बेटी राशा भी वेकेशन से कई सारे फोटोज और वीडियो शेयर कर रही हैं जिसमें उनके हॉट और बोल्ड अवतार को देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में राशा व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस में समुद्र किनारे खड़े होकर पोज देती नजर आईं।

पानी में मस्ती करती नजर आईं

राशा के इस किलर लुक पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं। उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो उनके पूरे वेकेशन की एक झलक दे रही है। इनमें से कुछ तस्वीर वहां के स्ट्रीट व्यू की हैं। जबकि कुछ अन्य फोटोज में वो पानी में स्वीमिंग करती और उसका लुत्फ उठाती नजर आईं। फोटोज में राशा नेचर का मजा लेते हुए सनबाथ करती हुई नजर आईं। उनकी ड्रेस के साथ सफेद कलर का चश्मा उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। राशा की इन तस्वीरों को देखकर लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, 'पहाड़ों में भी ऐसी ब्यूटी नहीं है अब तो।' एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया– 'हमेशा की तरह गार्जियस, ब्यूटीफुल क्वीन। लवली सुंदर प्रिंसेज।' तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'क्या खूबसूरती है।'

बैंडिट क्वीन' से कव्वाली गवाना चाहते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स, शेखर कपूर को दी थी अजीबोगरीब सलाह

सीमा बिश्वास ने निभाया था फूलन देवी का किरदार
हदी सिनेमा की विवादित फिल्मों में शुमार बैंडिट क्वीन
मनोज बाजपेयी ने बैंडिट क्वीन से किया था डेब्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माथे पर लाल कपड़ा, तन पर वर्दी और हाथ में बंदूक लिए बीहड़ की बागी की देखकर अच्छे–अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते थे। खुद पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाने वाली डाकू फूलन देवी के बारे में खूब चर्चा की जाती है। फूलन के जीवन पर 30 साल पहले निर्देशक शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई थी, यही वही शेखर हैं, जो जादुई घड़ी के साथ अनिल कपूर को मिस्टर इंडिया बना चुके थे। शेखर कपूर ने एक बार बताया था कि सच्ची कहानी पर आधारित बैंडिट क्वीन डिस्ट्रीब्यूटर्स कव्वाली चाहते थे, वो भी फूलन देवी के किरदार पर। इस सुझाव से शेखर भी हक्के–बक्के रह गये थे। आइए, इसे डिटेल में जानते हैं।

30 साल पहले डाकू फूलन देवी के जीवन पर फिल्म बैंडिट क्वीन को बनाया गया था। मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने फूलन देवी की कहानी को बड़े पर्दे पर बखूबी पेश किया। हालांकि विवादों के चलते इसे बाद में बैन कर दिया गया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से शेखर को बैंडिट क्वीन में कव्वाली रखने की सलाह मिली थी।

बैंडिट क्वीन को लेकर शेखर को मिली थी ये सलाह

1994 में जब बैंडिट क्वीन को बड़े पर्दे पर उतारा गया था तो इस मूवी ने बंपर सफलता हासिल की। अभिनेत्री सीमा बिस्वास ने फूलन देवी के किरदार को शानदार अदाकारी के दम पर अमर कर दिया। हालांकि, इस बात में कोई दोराय नहीं कि बतौर डायरेक्टर शेखर कपूर ने फूलन देवी की कहानी को सिनेमाघरों में पेश करने के लिए जीतोड़ मेहनत की। वाइल्ड फिल्म्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर शेखर का एक पुराना इंटरव्यू मौजूद है, जिसमें वह बैंडिट क्वीन की शूटिंग के दौरान का एक मजेदार किस्सा सुनाते नजर आए थे। इंडस्ट्री में स्टारडम कल्चर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था– जब आप मंदिर में जाते हैं तो सुकून शांति से पूजा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीकर वहां आपसे कहे क्या कर रहे हो ये, ऐसे होती है पूजा तो सब खंडित हो जाता है। ऐसे ही फिल्ममेकिंग में मुझे लोगों की गैर जरूरी सलाह पसंद नहीं है। बैंडिट क्वीन के सेट पर भी ऐसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुझे फिल्म में कव्वाली एड करने को कहा, मैंने उनसे कंडीशन पूछी तो उन्होंने बताया कि जब फूलन देवी (सीमा बिस्वास) डाका डालने जाएगी तो वो कव्वाली गाते हुए जाएगी और पीछे से आकर विक्रम मल्लाह (निर्मल पांडेय) अपना काम करेंगे। इस सुझाव को शेखर ने फौरन सिरे से खारिज कर दिया था। जरा सोचिए, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मान लेते तो बैंडिट क्वीन फिल्म कैसी दिखती।

बैन हो गई थी बैंडिट क्वीन

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की विवादित फिल्मों की सूची में बैंडिट क्वीन का नाम भी शामिल होता है। कुछ दिन बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद शेखर कपूर की इस फिल्म को बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिल्म में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, न्यूड सीन्स, आपत्तिजनक दृश्य और जातीय भेदभाव जैसे मसलों को प्रदर्शित किया गया। इस कारण बैंडिट क्वीन पर फुल स्टॉप लगा दिया गया।

ओटीटी पर मौजूद है बैंडिट क्वीन

बेशक सिनेमाघरों से बैंडिट क्वीन को बैन कर दिया गया हो, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यब पर आज भी सीमा बिश्वास की ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। अमेजन प्राइम वीडियो पर बैंडिट क्वीन मौजूद है, जिस पर आप इसे देख सकते हैं। मालूम हो कि बैंडिट क्वीन फिल्म के जरिए अभिनेता मनोज बाजपेयी ने हिंदी सिनेमा में बतौर कलाकार कदम रखा था।

24 साल की एक्ट्रेस ने खोला बालीवुड का काला चिट्ठा

दिल्ली। टेलीविजन से लेकर ओटीटी और फिल्मों तक एक्ट्रेस महिमा मकवाना ने लंबा सफर तय किया है। महिमा मकवाना ने हाल ही में करण जौहर के शोटाइम में देखा गया था जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, राजीव खंडेलवाल और मौनी रॉय के साथ स्क्रीन शेयर की थी। यह शो बॉलीवुड में पर्दे के पीछे होने वाले सत्ता संघर्ष और राजनीति को दिखाता है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में असल में बॉलीवुड में उन्हें क्या–क्या सामना करना पड़ा है। 24 वर्षीय महिमा मकवाना ने कहा है कि शोबिज की दुनिया में उन्हें पॉलटिक्स का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ पहले अलग तरह से व्यवहार किया जाता था। महिमा ने कहा कि इस इंडस्ट्री में लोग कहां से आते हैं, इस आधार पर लोगों से बर्ताव किया जाता है। महिमा मकवाना ने कहा, ''पॉलटिक्स का सामना किया है। मैंने ऐसी चीजों का सामना किया है जो थोड़ी अनुचित थीं। आपको यह भी नहीं पता होता कि आपको क्यों बदला जा रहा है। आपको यह भी नहीं पता होता कि आपके साथ एक खास तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है।'' महिमा मकवाना ने कहा, ''इस इंडस्ट्री में 'पैसा और पॉवर' के बिना कुछ नहीं चलता है। यहां 'पैसा और पॉवर' ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस इंडस्ट्री में लोग एक–दूसरे का स्टैंडर्ड देखकर बात करते हैं। पैसा, पॉवर और कंट्रोल यहां मायने रखता है। लेकिन मायने ये रखता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं।''महिमा मकवाना ने कहा, ''मुझे लगता है कि आखिरकार यह काम ही है जो बोलता है और आपका स्टैंड लेता है। क्योंकि देखिए, आप यह नहीं बदल सकते कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन आप केवल यह बदल सकते हैं कि आप खुद को इस बात से कैसे अलग करते हैं कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए उनकी सोच पर अपने–आप पर हावी मत होने दीजिए।''महिमा मकवाना ने यह भी स्वीकार किया कि,''इंडस्ट्री में इस तरह की राजनीति से दिल टूट जाता है। अभी भी, ऐसे दिन आते हैं जब मेरा दिल टूट जाता है। जाहिर है, एक एक्ट्रेस के तौर पर, मैं अपने काम को लेकर स्वार्थी हूं। मैं हमेशा ये सोचती हूं कि कैसे मैं कौन सा काम, अच्छे तरीके से कर सकती हूं।'' महिमा मकवाना ने आगे कहा कि, जिस तरह से कभी–कभी एक्टर और एक्ट्रेस से बर्ताव किया जाता है, जिस तरह से कभी–कभी मेरे साथ पेश आया जाता है, लोग आपको तवज्जो नहीं देते, आपके काम को जरूरी नहीं समझते हैं, तो आपका मन खराब हो जाता है और आप उदास महसूस करने लगते हैं। यह आपको बहुत सी चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है।''महिमा मकवाना ने कहा कि, ''कभी–कभी आपको खुद पर शक होने लगता है कि कहीं आपका काम तो ठीक नहीं है। किन आपको बस धैर्य रखना है,।

निकिता दत्ता ने लेटेस्ट लुक से इंटरनेट पर बरपाया कहर

सिंपल सूट पहन सादगी भरे अंदाज से लूटी महफिल कबीर सिंह फेम निकिता दत्ता आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं। उनका हर एक लुक सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा देता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक में फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनकी कातिल अदाएं देखकर फैंस लट्टू हो गए हैं और साथ ही उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

शमा सिकंदर की अदाएं

अदाओं को यूजर्स हुए घायल टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर हमेशा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स से फैंस के बीच चर्चाएं बटोरती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में उन्होंने अपना लेटेस्ट हाट फोटोशूट फैंस के बीच शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिया है। इन तस्वीरों में उनका एलिगेंट और ब्यूटिफुल लुक देखकर फैंस आहें भरने लगे हैं।

पेरिस में दिखेगा
युवा भारत का जोश

विलीना–निकहत की तैयारी के लिए कोच धर्मेंद्र ने किया त्याग

नहीं हुए बेटे की शादी में शामिल

नई दिल्ली । 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य जीतने वाले धर्मेंद्र ने शादी में नहीं आने का फैसला लिया। वह मंगलवार को जर्मनी से टीम के साथ पेरिस के लिए रवाना हो गए। धर्मेंद्र शादी में थे नहीं, लेकिन उनकी पत्नी मीनू ने हर रस्म में वीडियो कॉल के जरिये उनकी मौजूदगी बनाए रखी है। पेरिस ओलंपिक में देश के मुक्केबाजों को पदक दिलाने के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम के कोच और अपने समय के नामी मुक्केबाज अर्जुन अवॉर्डी धर्मेंद्र यादव ने अपने बेटे की शादी छोड़ दी।

बुलंदशहर के धर्मेंद्र के सामने बीते सप्ताह बड़ा धर्मसंकट खड़ा हो गया कि वह बेटे की शादी में शामिल हों या सारब्रुकेन (जर्मनी) में भारतीय मुक्केबाजी टीम की तैयारियां छोड़ दें। यह उलझन सिर्फ शादी तक सीमित नहीं थी। देश के पहले पेशेवर बॉक्सर धर्मेंद्र की मां की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें आईसीयू में दाखिल कराना पड़ा था।

मां के कहने पर ही पोते की शादी आनन–फानन में करनी पड़ रही थी। ओलंपिक से ठीक पहले धर्मेंद्र का तैयारियां छोड़ना ठीक नहीं था। उनकी पत्नी और बेटे ने कहा वह राष्ट्रीय कोच की भूमिका निभाएं, बाकी सब वे संभाल लेंगे।

निकहत से लेकर अंतिम तक, 70 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे ओलंपिक

स्पोर्ट्स डेस्क। 117 सदस्यीय दल में 47 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें एक या उससे अधिक ओलंपिक खेलने का अनुभव है। इनमें पुरुष हॉकी टीम समेत पांच पदक विजेता भी शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में इस बार युवा भारत का जोश दिखेगा। 117 सदस्यीय भारतीय दल में 70 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में शिरकत करने जा रहे हैं। इनमें 29 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मुक्केबाज निकहत जरीन, पहलवान अंतिम पंघाल, रीतिका, एथलीट ज्योति याराजी, शूटर सिफ्त कौर समरा, रमिता, रिद्म सांगवान ऐसी बेटियां हैं जो पहली बार खेलते हुए देश को ओलंपिक पदक दिलाने का दम रखती हैं। पहलवान अमन सहरावत, जेवलिन थ्रोअर किशोर जेना, तीरंदाज बी धीरज, मुक्केबाज निशांत देव, शूटर सरबजोत सिंह, संदीप सिंह, अर्जुन बबूटा, अर्जुन चीमा, अनीश में भी पहली बार ओलंपिक में खेलते कुछ कर गुजरने का दम है।

47 खिलाड़ियों को है ओलंपिक खेलने का अनुभव

117 सदस्यीय दल में 47 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें एक या उससे अधिक ओलंपिक खेलने का अनुभव है। इनमें पुरुष हॉकी टीम समेत पांच पदक विजेता भी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक जीते थे। इनमें स्वर्ण जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रजत जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, कांस्य जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना, शटलर पीवी सिंधू के अलावा पुरुष हॉकी टीम पदक के लिए एक बार फिर जोर–आज माइश करेंगे।

ध्वज वाहक 42 वर्ष के शरत का पांचवां ओलं पक

भारतीय दल में अनुभव की भी कमी नहीं है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल पांचवां ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। वह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक भी होंगे। वहीं तीरंदाज तरुणदीप रॉय, दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह का यह चौथा ओलंपिक होगा।

44 के बोपन्ना सबसे उम्रदराज, 14 की दिनिधि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी

भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना होंगे, जबकि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 14 वर्षीय तैराक दिनिधि देसिंघु होंगी। दिनिधि ओलंपिक में खेलने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। इससे पहले 11 वर्ष की उम्र में तैराक आरती साहा ने 1952 के ओलंपिक में शिरकत की थी। दल में तीन खिलाड़ी बोपन्ना, शरत कमल (42) और तरुणदीप रॉय (40) ऐसे हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है। ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडाईमान (37), हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश (36), गोल्फर गगनजीत भुल्लर (36), एथलीट एमआर पूवम्मा (34), शटलर अश्वनी पोनप्पा (34), शटलर एचएस प्रणय (32) अन्य उम्रदराज खिलाड़ी हैं।

हाकी टीम में 12 ओलंपियन

पेरिस के लिए हॉकी की मुख्य टीम में 16 और तीन खिलाड़ी रिजर्व के तौर पर चुने गए हैं। इनमें 12 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगा। इसके बाद टीम 29 जुलाई को अर्जेंटीना से भिड़ेगी। इसके बाद अगले दिन आयरलैंड और एक अगस्त को गत विजेता बेल्जियम से भारत का सामना होगा। टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ दो अगस्त को भारत को खेलना है।

तैराक धिनिधि पेरिस में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय

स्पोर्ट्स डेस्क। पेरिस ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और खेलों के इस महाकुंभ को शुरू होने में अब तीन दिन शेष रह गए हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए 117 सदस्यीय दल भेजा है जिन पर पदक लाने का जिम्मा रहेगा। भारत के लिए इस बार महिला तैराक धिनिधि देसिंघू पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 14 साल की धिनिधि 200 मीटर फ्री स्टाइल में भाग लेंगी। भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी 14 साल की धिनिधि देसिंघू हैं। वह सीधे क्वालिफाई नहीं कर सकी थीं लेकिन यूनिवर्सिलिटी कोटे के तहत उन्हें भाग लेने का मौका मिला है। वह विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। वैसे भारत की ओर से सबसे युवा ओलंपियन बनने का रिकॉर्ड आरती साहा के नाम है जिन्होंने 11 साल और 10 महीने की उम्र में हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था।

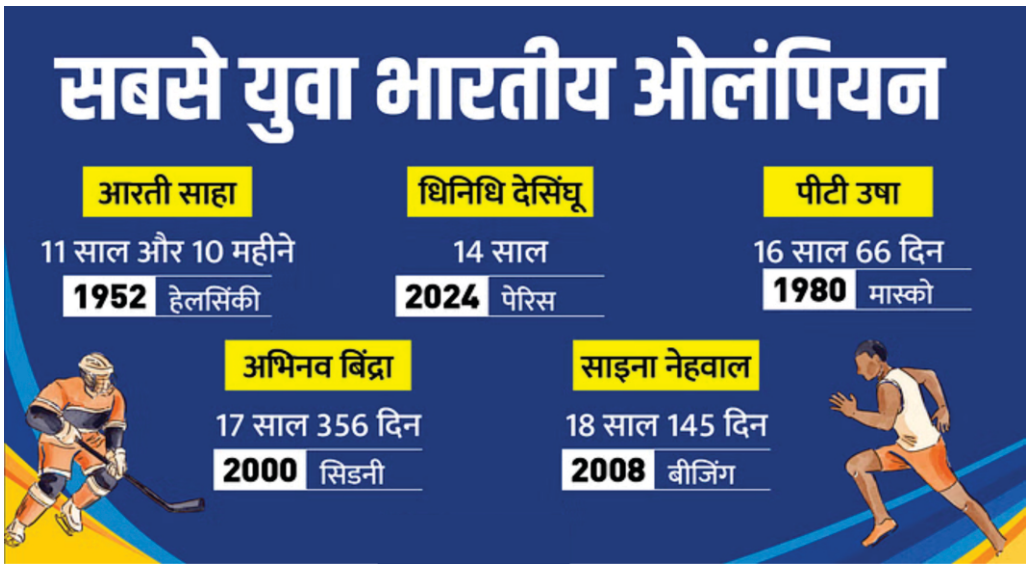

कनाडा की जिल खेलेंगी 61 की उम्र में अपना पहला ओलंपिक

26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक में जहां ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवारी टीम में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल 69 साल की मैरी हाना शामिल हैं तो कनाडा की घुड़सवारी टीम में जिल इरविंग भी हैं जो 61 साल की हो चुकी हैं और अपना पहला ओलंपिक खेलेंगी। जिल को तो टोक्यो ओलंपिक में ही खेलना था लेकिन कोरोना के कारण खेल एक साल के लिए खिसक गए और तब तक उनके घोड़े की भाग लेने की उम्र निकल गई। अब घोड़ा बदल गया पर जिल भी वही हैं और खेलने का जज्बा भी वही है। मैरी तो पोते–पोतियों वाली हैं लेकिन घुड़सवारी नहीं छोड़ी है। जिस उम्र में आम लोग लठिया और खटिया पकड़ लेते हैं मैरी पूरी शान से तनकर घोड़े पर ऐड़ लगाती हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह इस बार अपना सातवां ओलंपिक खेलेंगी। वह ड्रेसेज में हिस्सा लेती हैं। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में वह 66 साल की उम्र में भाग लेने वालीं सबसे उम्रदराज थीं।

11 साल की चीनी स्केटबोर्ड खिलाड़ी सबसे युवा

पेरिस में सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो चीन की स्केटबोर्ड खिलाड़ी झेंग हाओहाओ महज 11 साल की हैं और चीन की सबसे युवा ओलंपियन हैं। उन्होंने बुडापोस्ट ओलंपिक क्वालिफायर सीरीज में पेरिस के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। सात साल की उम्र में उन्हें एक स्केटबोर्ड जन्मदिन के तोहफे के रूप में मिला था और उसके बाद यह उनका जुनून बन गया। स्केटबोर्ड में टोक्यो ओलंपिक में 13 साल की स्काई ब्राउन ने कांस्य पदक जीता था और देश की सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बनी थीं। इस बार वह 16 साल की उम्र में फिर से ओलंपिक में उतर रही हैं। उनकी मां जापान की हैं और पिता ब्रिटेन के हैं।

भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी 14 साल की धिनिधि देलसयू हैं। वह सीधे क्वालिफाई नहीं कर सकी थीं लेकिन यूनिवृसलिटी कोटे के तहत उन्हें भाग लेने का मौका मिला है।

– मनु भाकर

रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज भारतीय

44 वर्ष और चार महीने के बोपन्ना पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। वह तीसरा ओलंपिक खेल रहे हैं और पुरुष युगल में श्रीराम बालाजी के साथ उतरेंगे। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में महेश भूपति के साथ पदार्पण किया था। रियो ओलंपिक में वह लिएंडर पेस के साथ दूसरे दौर में हार गए। मिश्रित युगल में वह और सानिया मिर्जा कांस्य पदक से एक जीत दूर पहुंचे थे। जनवरी में एटीपी युगल रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे बोपन्ना ने 43 वर्ष की उम्र में आस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। वह सिडनी जैकब के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी हैं। जैब ने 44 वर्ष 267 दिन की उम्र में पेरिस ओलंपिक 1924 में पुरुष युगल खेला था। भारत के सबसे उम्रदराज ओलंपियन स्कीट निशानेबाज भीम सिंह बहादुर हैं जिन्होंने 1976 मांट्रियल ओलंपिक में भाग लिया तब वह 66 वर्ष के थे। भारतीय दल में 42 वर्ष के अचंत शरत कमल और 40 वर्ष के तीरंदाज तरुणदीप राय भी हैं।

शूटर मनु भाकर और एथलीट पारुल चौधरी दो-दो इवेंट में लेंगी हिस्सा

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिन:– 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।